राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 312 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार ,20 मई 2021, मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

बच्चों के वैक्सीन ट्रायल पर कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली , (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्टने दो से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों पर कौवक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लीनिक्ल ट्रायल को अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार तथा भारत बायोटेक से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायाधीश ज्योति सिंह की बेंच ने संजीव कुमार की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। इस याचिका में कहा गया है कि क्लीनिक्ल ट्रायल को अनुमति दिया जाना अवैध और निरंकुश है।

ललित शाक्यवार होंगे मुरैना के नए एसपी

भोपाल, (प्रसं)। राज्य शासन ने मुरैना के पुलिस

अधीक्षक को हटाकर उनके स्थान पर ललित शाक्यवार को मुरैना का नया पुलिस अधीक्षक पदस्थ किया है। वहीं मुरैना एसपी सुनील कुमार पांडे को पुलिस मुख्यालय भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ किया है। गृह विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ललित शाक्यवार वर्तमान में पुलिस मुख्यालय भोपाल में डीआईजी के पद पर पदस्थ थे।

झारखंड में नदी में गिरा इंजन, ट्रेन हादसा टला

बानो, (एजेंसी)।झारखंड में सिमडेगा-रांची मार्ग पर कनरवा स्टेशन के पास बुधवार की रात बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। हटिया राउरकेला पैसेंजर ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई। पटरियों से उतरने के बाद अनियंत्रित हुआ इंजन बोगियों से अलग होकर नदी में गिर गया। संयोग से बोगियां इंजन से अलग होने के बाद भी पलटी नहीं और न ही एक दूसरे पर चढ़ीं। घटना के समय ट्रेन में 200 यात्री सवार थे। बुधवार की रात नौ बजे पैसेंजर ट्रेन हटिया से राउरकेला जा रही थी। इसी दौरान साउथ केबिन देवनदी के समीप ट्रेन पटरी से उतर गई और इंजन बोगियों से अलग हो गया।

कालरा की जमानत पर आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए नवनीत कालरा ने जमानत के लिए साकेत कोर्ट में अर्जी लगाई है। साकेत कोर्ट कालरा की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। फिलहाल नवनीत कालरा दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। दो दिन पहले नवनीत कालरा को गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पुलिस की तरफ से पांच दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई थी लेकिन कोर्ट ने उनकी तीन दिन की कस्टडी पुलिस को दे दी थी।

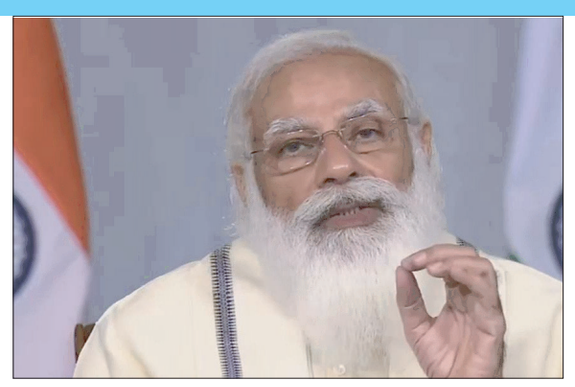

किसानों के पक्ष में केंद्र का ऐतिहासिक फैसला! अब डीएपी खाद के हर बैग पर मिलेगी 1200 रुपये की सब्सिडी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तय किया है कि डीएपी फर्टिलाइजर के एक बैग पर अब किसानों को 1200 रुपये की छूट दी जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में डीएपी फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली सब्सिडी में 140 फीसदी इजाफे का फैसला लिया गया. इससे किसानों को 2400 रुपये में मिलने वाला डीएपी फर्टिलाइजर का एक बैग अब 1200 रुपये में ही मिल जाएगा. हालांकि, इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को सब्सिडी के मद में 14,775 करोड़ रुपेय अतिरिक्त खर्च होंगे. बता दें कि अब तक डीएपी फर्टिलाइजर के एक बैग पर किसानों को 500 रुपये की ही छूट मिलती थी.

प्रधानमंत्री मोदी ने खाद कीमतों के मुद्दे पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया की बढ़ती कीमतों के कारण खाद की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए. इसके बाद डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से 140 फीसदी बढ़ाकर 1200 रुपये करने का फैसला लिया गया. दूसरे शब्दों में समझें तो अब किसानों को डीएपी खाद 1200 रुपये के पुराने मूल्य पर ही मिलेगी. साथ ही मूल्य वृद्धि का सारा अतिभार केंद्र सरकार उठाएगी. बता दें कि प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एकबार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसानों को नहीं झेलना पड़ा मूल्य वृद्धि का बोझ- डीएपी खाद की एक बोरी की वास्तविक कीमत पिछले साल 1,700 रुपये थी. इसमें केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी. इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थीं. हाल में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 60 से 70 फीसदी तक बढ़ गई हैं. सरकार के मुताबिक, एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपये है, जिसे खाद कंपनियों की ओर से 500 रुपये की सब्सिडी घटाकर 1900 रुपये में बेचा जाता है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगा कि किसानों को मूल्य वृद्धि का असर न झेलना पड़े.

कांग्रेस ने लगाया था किसानों पर 20 हजार करोड़ का बोझ डालने का आरोप- केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है. अब खरीफ सीजन में भारत सरकार इस मद में 94,775 करोड़ रुपये खर्च करेगी. अक्षय तृतीया के मौके पर पीएम-किसान के तहत किसानों के खाते में 20,667 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर करने के बाद किसानों के हित में केंद्र सरकार का यह दूसरा बड़ा फैसला है. बता दें कि आज ही कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सरकार ने डीएपी खाद की कीमतों को बढ़ाकर किसानो पर 20,000 करोड़ का बोझ डाल दिया है. कांग्रेस के मुताबिक, डीएपी खाद की कीमत में 700 रुपये प्रति बैग की बढ़ोतरी की गई है. साथ ही कहा था कि इससे कंपनियों को 13,000 करोड़ रुपये का मुनाफा होगा.

केंद्र ने राज्यों को लिखा पत्र, कहा- 5.86 करोड़ वैक्सीन डोज फ्री में दी जाएगी

नई दिल्ली । कोरोना वायरस के खिलाफ देश में टीकाकरण तेजी से जारी है।देश में कोरोना टीकाकरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने आज अपना प्लान बताया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है। भारत सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है। इसमें राज्यों में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराए जाने का पूरा विवरण साझा किया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत सरकार के माध्यम से मई और जून के पहले पखवाड़े(15 दिन) के दौरान ष्टह्रङ्कढ्ढष्ठ वैक्सीन खुराक के आवंटन और वैक्सीन की खुराक की उपलब्धता पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है, जो मई और जून 2021 के दौरान सीधे राज्यों और निजी अस्पतालों द्वारा खरीदी जा सकती हैं। भारत सरकार ने जानकारी दी है कि सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किए गए अग्रिम प्लान के अनुसार, 1 मई 2021 से 15 जून 2021 तक भारत सरकार द्वारा राज्यों को कुल 5,86,29,000 वैक्सीन की डोज़ निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही भारत सरकार ने कहा कि इसके अलावा, वैक्सीन निर्माताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सीधी खरीद के लिए जून 2021 के अंत तक कुल 4,87,55,000 खुराकें भी उपलब्ध होंगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी कोरोना वैक्सीन की दो करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। इन्हें अगले तीन दिन के भीतर 51लाख और डोज मिल जाएंगी।मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20 करोड़ 76 लाख 10 हजार 230 डोज बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराया है। सोमवार सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंक़ड़ों के मुताबिक, इनमें से 16 मई तक 18 करोड़ 71 लाख 13 हजार 705 डोज का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसमें बर्बाद हुई डोज भी शामिल हैं।

इस तरह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी दो करोड़ चार लाख 96 हजार 525 डोज उपलब्ध हैं।

नारद मामले में आरोपितों नहीं मिल सकी जमानत, आज हाईकोर्ट में फिर सुनवाई

कोलकाता । नारद स्टिंग मामले में गिरफ्तार बंगाल के हेवीवेट मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल विधायक मदन और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को फिलहाल जेल हिरासत में ही रहना पड़ेगा। बुधवार को इन नेताओं को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। इन नेताओं की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज करीब ढाई घंटे तक वर्चुअल सुनवाई हुई। कल यानी गुरुवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी। दूसरी सीबीआइ ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कानून मंत्री मलय घटक को कलकत्ता हाई कोर्ट में दाखिल अपनी उस याचिका में पक्ष बनाया है, जिसमें इस केस को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका पर भी बुधवार को फैसला नहीं हो पाया। कल फिर सुनवाई होगी।

बुधवार को सुनवाई के दौरान इन नेताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि अभी कोरोना महामारी जैसे संकट के समय में हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि सीबीआइ की ओर से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ से जमानत का विरोध किया। सीबीआइ की ओर से दलील दी गई कि ये सभी नेता बहुत प्रभावशाली हैं। बाहर आने से ये मामले को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआइ ने इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जांच एजेंसी के कार्यालय में घंटों धरना देने और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बाहर घेराव करने एवं केंद्रीय बलों पर पथराव करने का मुद्दा भी उठाया।

बताते चलें कि सीबीआइ ने इन नेताओं को सोमवार सुबह गिरफ्तार किया था। सीबीआइ अदालत ने उसी दिन शाम में इन सभी को जमानत दे दी थी, लेकिन देर रात में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाते हुए 19 मई तक जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया था।

सीबीआइ के खिलाफ कानूनी कदम उठाने पर विचार कर रहा विधानसभा सचिवालय

नारद स्टिंग ऑपरेशन कांड में विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बगैर विधायकों की गिरफ्तारी को लेकर विधानसभा सचिवालय सीबीआइ के खिलाफ कानूनी कदम उठाने पर विचार कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा कि तीनों विधायकों (जिनमें से दो राज्य के मंत्री भी हैं) को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, वह गैरकानूनी है। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई।

सीबीआइ के खिलाफ दर्ज कराई एफआइआर- नारद स्टिंग कांड में बंगाल के दो मंत्री व विधायक की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए तृणमूल कांग्रेस की महिला इकाई की अध्यक्ष व वरिष्ठ मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को सीबीआइ अधिकारियों के खिलाफ महानगर के गरियाहाट थाने में एफआइआर दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है, ''तीनों नेता सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम व मदन मित्रा बंगाल विधानसभा के सदस्य हैं और विधानसभा अध्यक्ष से उनकी गिरफ्तारी से पहले परामर्श और अनुमति ली जानी चाहिए, जो इस मामले में नहीं किया गया।''

सीबीआइ की याचिका में ममता को भी पक्ष बनाया गया

-नारद स्टिंग कांड में तृणमूल कांग्रेस के हेवीवेट नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआइ ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कानून मंत्री मलय घटक को कलकत्ता हाई कोर्ट में दाखिल अपनी उस याचिका में पक्ष बनाया है, जिसमें इस केस को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने ममता और घटक के अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद तथा वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी को भी अपनी याचिका में पक्ष बनाया है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। हालांकि हाई कोर्ट ने बुधवार को कोई फैसला नहीं सुनाया। अब इस मामले पर गुरुवार को हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी।

नारद स्टिंग मामले में सीबीआइ भाजपा नेता तथा पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद सुवेंदु अधिकारी, तृणमूल सांसद सौगत रॉय, प्रसून बनर्जी और काकोली घोष दस्तीदार पर मुकदमा चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को फिर पत्र लिखने जा रही है। सीबीआइ सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अप्रैल 2019 में अभियोजन के लिए लोकसभा अध्यक्ष से मंजूरी मांगी थी, जो अभी तक तक नहीं मिली है।

गुजरात को प्रधानमंत्री ने दी 1000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात में चक्रवाती तूफान टाक्टे के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया और तत्काल राहत कार्यों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। इस क्रम में उन्होंने गुजरात व दीव के प्रभावित इलाकों उना, जाफराबाद, महुआ का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में मुख्यमंत्री विजय रुपाणी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिसमें राहत व पुनर्वास कार्यक्रमों के संबंध में उठाए गए कदमों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दमन व दीव, दादर और नागर हवेली में आए इस तूफान के कारण मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे के तौर पर 2 लाख की रकम का ऐलान किया है और घायलों को 50 हजार रुपये देने की बात कही है।

प्रधानमंत्री ने राज्य में तत्काल राहत गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्य के हालात की समीक्षा और नुकसान का आकलन करने के लिए एक टीम का गठन करेगी।

इस आकलन के आधार पर राज्य को और भी सहायता मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री ने राज्य की जनता को आश्वासन दिया कि इस कठिन दौर में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ है और प्रभावित इलाकों में जिंदगी को बहाल करने के लिए हर संभव मदद मुहैया कराएगी। यहां इस तूफान के कारण अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है।

गुजरात के दौरे में प्रधानमंत्री ने महामारी के कारण राज्य के हालात का भी जायजा लिया। राज्य प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री को हालात से अवगत कराया गया और यह भी जानकारी दी गई कि इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने तूफान प्रभावित इलाकों की जनता के प्रति दुख प्रकट किया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी से बात की और चक्रवाती तूफान से राज्य में पैदा हालात का जायजा लिया, क्योंकि सोमवार रात वहां तूफान के कारण भूस्खलन भी हुआ।

बता दें कि तूफान आज कमजोर हो गया है, लेकिन हवा अभी भी 125 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जारी है। उत्तरी भारत के कई इलाकों में इस तूफान का असर देख गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कई इलाकों में इसके कारण बारिश हो रही है।

तटीय इलाकों में भारी नुकसान, 45 मरे –गुजरात में चक्रवात टाक्टे ने तबाही मचाई है। यहां अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। चक्रवात से हुए नुकसान के सर्वे के बाद सरकार इसका मुआवजा देगी। गुजरात में बिजली के खंभे तथा पेड़ उखड़ गए तथा कई घरों व सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है।

केजरीवाल को मिली जयशंकर की नसीहत से सहमत सिंगापुर बोला- भारत के स्पष्टीकरण से संतुष्ट

नई दिल्ली । भारत की राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दिए बयान पर फिलहाल घमासान जारी है। केजरीवाल के ट्वीट पर सिंगापुर सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इस बाबत सिंगापुर की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब भी किया गया। वहीं, केजरीवाल को विदेश मामलों में दखल न देने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी नसीहत दी। अब भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने सीएम केजरीवाल के मामले पर बात करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमें यह देखकर खुशी हुई कि विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने जो तीन बातें कहीं, वो सराहनीय थी।

उन्होंने कहा, सिंगापुर और भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से साथ हैं। दिल्ली के सीएम भारत के लिए नहीं बोलते हैं।...और तीसरी बात यह कि दिल्ली सीएम की टिप्पणी गैर-जिम्मेदाराना थी। वोंग ने आगे कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है, मैं कहूंगा कि हम इस प्रकरण को समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने इस बारे में जो बताया हम उन आश्वासनों से प्रसन्न हैं।

सिंगापुर के उचायुक्त ने कहा, यह (दिल्ली के सीएम की टिप्पणी) हमारी (भारत-सिंगापुर) कोविड के खिलाफ लड़ाई को प्रभावित नहीं करेगी। जैसा कि आज और पहले भी देखा गया है कि हमारे में चिकित्सा सहायता की जा रही है। हम एक साथ काम कर रहे हैं। महामारी की कोई सीमा या राजनीतिक रंग नहीं होता।

साइमन वोंग ने बताया, सिंगापुर में, हमारे पास गलत सूचना को कम करने के लिए ऑनलाइन फर्जीवाड़ा और हेरफेर अधिनियम से सुरक्षा है और हम सीएम (दिल्ली) द्वारा किए गए दावों पर पीओएफएमए लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हालांकि, हम भारत सरकार के स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं। बता दें कि सिंगापुर ने फर्जी खबरों के प्रकाशन को अपराध बनाने वाला एक कानून पारित किया है। इस कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की सजा हो सकती है और उन पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सिंगापुर सरकार वैज्ञानिक दृष्टि से वायरस और इसके प्रकारों से निपटना पसंद करती है। हम वायरस को कोई भौगोलिक नाम नहीं देने की डब्ल्यूएचओ की सिफारिश का बारीकी से पालन करते हैं। हम किसी पर उंगली उठाने से यादा वैज्ञानिक पहलू पर ध्यान देते हैं।

कांग्रेस रिसर्च टीम की सदस्य सौम्या ने बनाई है टूलकिट, भाजपा ने पेश किया सुबूत

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने के लिए मोदी वैरिएंट जैसे शब्दों के उपयोग, विदेशी मीडिया की मदद जैसी सलाहों वाली टूलकिट को यूं तो कांग्रेस नकार रही है लेकिन बुधवार को भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुबूतों के साथ दावा किया कि यह कांग्रेस रिसर्च विंग से जुड़ी और पार्टी के शीर्ष नेताओं की करीबी सौम्या वर्मा ने तैयार की थी। संबित ने राहुल गांधी के साथ फोटो में खड़ी सौम्या की तस्वीर भी जारी की है। वहीं भाजपा के अन्य नेताओं ने ट्वीट कर बताया कि सौम्या, 2019 में कांग्रेस का घोषणापत्र बनाने में भी शामिल थी।

एक दिन पहले कांग्रेस ने थाने में भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर आरोप लगाया था कि टूलकिट भाजपा ने ही बनाई थी। जवाब में पात्रा ने सौम्या वर्मा और कांग्रेस के साथ उसके संबंधों की पूरी दास्तान सामने रख दी। उसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें वायरल हुई जिसमें यह सामने आया कि सौम्या न सिर्फ कांग्रेस की रिसर्च विंग में हैं बल्कि काफी प्रभावशाली भी हैं। पिछले आम चुनाव में पार्टी का घोषणापत्र तैयार करने में भी उनकी भूमिका रही है। यह मामला उजागर होने के बाद सौम्या ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट बंद कर दिए।

संजुक्ता बसु ने टूलकिट को सही माना- भाजपा सोशल मीडिया के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी इंटरनेट मीडिया टीम की सदस्य संजुक्ता बसु का एक ट्वीट पेश किया है जिसमे उन्होंने टूलकिट को सही मानते हुए कहा- विरोधी की छवि को ध्वस्त करना विपक्ष का काम है। कांग्रेस आखिरकार अच्छा काम कर रही है।

डॉ. हर्षवर्धन ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में नए पीएसए का निरीक्षण करते हुए।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए इन कदमों की बदौलत कोरोना की दूसरी लहर में आई गिरावट

नई दिल्ली। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब गिरावट की ओर है। इस दौरान मामले 4 लाख से घटकर अब 2.67 लाख पर आ गए हैं। जानकारों की मानें तो यदि गिरावट का यही दौर जारी रहा और सब कुछ ठीक रहा तो एक सप्ताह के अंदर ये लहर चली जाएगी। आपको बता दें कि भारत में आई दूसरी लहर का प्रकोप पहले की तुलना में तीन गुना अधिक था। पहली लहर के दौरान भारत में सितंबर में एक दिन में अधिकतम 97 हजार मामले सामने आए थे।

दूसरी लहर में लगातार गिरावट आने के बाद भी जानकार इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि खतरा टल गया है। इस बीच कोरोना महामारी की तीसरी लहर की भी आशंका लगातार बनी हुई है। बहरहाल, तीसरी लहर को देखते हुए भी राज्य और केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियों को अधिक मजबूती के साथ करने में कमर कस ली है। वहीं दूसरी लहर में आ रही गिरावट की वजह भी केंद्र और राज्यों के लिए गए कई ऐसे फैसले रहे हैं जिनकी बदौलत ऐसा संभव हो सका है।

आपको यहां पर ये याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि कुछ समय पहले ही केंद्र ने राज्यों को ये अधिकार दिया था कि वो महामारी को देखते हुए अपने यहां पर किसी भी स्तर पर कदम उठा सकते हैं। राज्यों ने इस अधिकार का भलीभांति उपयोग इस दौर में किया है। राज्यों ने इसके तहत जिलाधिकारियों को ये अधिकार दिया कि वो अपने स्तर पर कोरोना संक्रमण के मामले देखते हुए आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन तक लगाने का फैसला ले सकते हैं। ऐसा हुआ भी। महाराष्ट्र में इस तरह की चीजें देखने को मिली जहां पर जिला स्तरीय लॉकडाउन लगाया गया। इसके अलावा इसी तरह से कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में भी इसको अपनाया गया। केंद्र सरकार की ही बात करें तो इस दौर में प्रधानमंत्री ने लगातार महामारी का जायजा लिया और राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत जरूरत पड़ने पर महामारी से अधिक प्रभावित जिलों के डीएम तक से सीधी बातचीत की। उन्होंने कहा कि यदि उनका जिला इस महामारी पर काबू पाने में सफल हो सका तो उनकी बदौलत इस महामारी पर देशभर में विजय पाई जा सकेगी। इसके अलावा केंद्र की तरफ से समय समय पर दिशा-निर्देश भी राज्यों को दिए जाते रहे।

कोरोना दुनिया में:बीते दिन 6.08 लाख केस

13,833 मौतें; यूएस हेल्थ एजेंसी ने कहा- भारत मिले वैरिएंट पर अमेरिकी वैक्सीन असरदार

वॉशिंगटन। दुनियाभर में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। बीते दिन दुनिया में 6.08 लाख लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इस दौरान 13,833 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई। लगातार बढ़ता मौतों का आंकड़ा दुनियाभर के लिए चिंता का सबब बना हुआ है।

इस बीच अमेरिकी हेल्थ ऑफिसर्स ने दावा कि उनके यहां तैयार की गई कोरोना वैक्सीन सबसे पहले भारत में पाए गए वैरिएंट के खिलाफ कारगर है। इस स्ट्रेन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैरिएंट 'ऑफ कंसर्न' घोरूात कर रखा है।

B617 और B1618 दोनों वैरिएंट पर कारगर वैक्सीन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ एडवाइजर और US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अलर्जी एंड इंफेक्शियस डिसीज के डायरेक्टर डॉ. एंथनी फाउसी ने बताया मौजूदा दौर में उपलब्ध वैक्सीन जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह कम से कम आंशिक रूप से और शायद काफी हद तक सुरक्षात्मक होंगे। डेटा हमें बताते है कि हमारी वैक्सीन के जरिए दोनों वैरिएंट B617 और B1618 को खत्म किया गया है।

सिंगापुर में मिला नया स्ट्रेन बच्चों के लिए खतरनाक

सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। यह स्ट्रेन बच्चों पर ज्यादा असर डाल रहा है। ऐसे में वहां प्राइमरी-सैकेंडरी स्कूल और जूनियर कॉलेज बुधवार से बंद करने का फैसला लिया गया है। अब बच्चों को घर से ही वर्चुअली पढ़ाई करवाई जाएगी।

शिक्षा मंत्री चान चुन सिंग ने बताया कि वायरस के नए स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हैं और ऐसा लगता है कि ये बच्चों को ज्यादा अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। यह हम सभी के लिए चिंता की बात है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि नए वायरस से संक्रमित कोई भी बच्चा गंभीर रूप से बीमार नहीं है।

अब तक 16.48 करोड़ केस:दुनिया में कोरोना के अब तक 16.48 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 34.18 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14.50 करोड़ लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1.76 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें 1.75 करोड़ लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं और एक लाख से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

वैक्सीन डिप्लोमेसी: बाइडेन ने भरा दम- चीन, रूस से 5 गुना ज्यादा टीके बांटेंगे, अब दानवीर बनने की होड़, बाइडेन का ज्यादा का वादा

वॉशिंगटन। महामारी के दौर में सबसे ज्यादा चर्चा वैक्सीन की है। ऐसी ही है- वैक्सीन डिप्लोमेसी, जिसमें जरूरतमंद देशों को टीके दिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें रूस और चीन के दबदबे ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति को चिंता में डाल दिया है। उन्हें डर है कि हर मामले में दुनिया का नेतृत्व करने वाला अमेरिका इसमें पिछड़ न जाए। शायद इसीलिए उन्होंने वैक्सीन डोनेशन प्लान की घोषणा की है। बाइडेन ने जरूरतमंद देशों को 8 करोड़ डोज दान देने का वादा किया है। उन्होंने कहा, 'यह किसी भी देश के मुकाबले अधिक हैं। यहां तक कि रूस और चीन की तुलना में भी 5 गुना ज्यादा हैं।' साथ ही कहा कि इसमें भी दुनिया का नेतृत्व हम ही करेंगे। इसमें 2 करोड़ डोज फाइजर, मॉडेर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के होंगे, जबकि बाकी 6 करोड़ डोज एस्ट्राजेनेका के। ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका अपने इस्तेमाल की वैक्सीन दूसरे देशों को देगा। बाइडेन ने कहा कि हम टीके इसलिए नहीं दे रहे हैं कि कोई देश हमारा समर्थन करें। वैक्सीन डोनेशन प्लान की घोषणा करते वक्त राष्ट्रपति बाइडेन रूस और चीन के दबदबे से चिंतित दिखे। इस पर बाइडेन ने कहा, 'हर जगह चीन और रूस के वैक्सीन के जरिए विश्व को प्रभावित करने की चर्चा है। हम अपने मूल्यों के हिसाब से दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं, जैसा दूसरे विश्व युद्ध में किया था। ऐसे ही वैक्सीन के मामले में भी हम नेतृत्व करेंगे।

पहली बार खुलासा: दुनिया का 90फीसदी सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा 100 कंपनियां पैदा कर रहीं; इनमें अमेरिका की डाउ, चीन की सिनोपेक भी

लंदन। मौजूदा वक्त में हमारे जरूरत की बाजार में मिलने वाली लगभग सभी चीजें किसी न किसी तरह के पैकेट में आती हैं। इनमें भी ज्यादातर की पैकेजिंग उस प्लास्टिक से होती है, जिसे हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं और उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसे हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं, जो पर्यावरण को तबाह करने और धरती की सेहत बिगाड़ने में सबसे बड़ा हिस्सेदार है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया भर में निकलने वाले इस तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे का 90त्न सिर्फ 100 कंपनियां पैदा कर रही हैं। वहीं दुनिया के आधे से ज्यादा कचरा सिर्फ 20 कंपनियां पैदा कर रही हैं और ये सभी पेट्रोकेमिकल से जुड़ी हैं। इनमें एक्सॉन मोबाइल, अमेरिका की डाउ केमिकल्स और चीन की पेट्रो कंपनी सिनोपेक भी शामिल है। दुनिया में पहली बार यह खुलासा हुआ है, जिसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट और मिंडेरू फाउंडेशन के कंसोर्टियम ने किया है। रिसर्च के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के पीछे काम कर रहे कॉरपोरेट नेटवर्क को भी खंगाला गया। इसके लिए दुनिया भर में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को कच्चा माल सप्लाई करने वाली एक हजार से ज्यादा कंपनियों का अध्ययन किया गया।

हथियारों की सौदेबाजी:इजरायल को 5.4 हजार करोड़ के हथियार देगा अमेरिका; डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन दोनों इजरायल के साथ, तुर्की भड़का

यरूशलम/वॉशिंगटन/अंकारा। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 10 दिन से जारी संघर्ष के बीच आम लोगों की जिंदगी बदहाल हो गई है। इजरायल के हवाई हमले में गाजा की इकलौती कोविड टेस्टिंग लैब बंद हो गई है। अधिकारियों का आरोप है कि इजरायल ने जानबूझकर इसे निशाना बनाया। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल को करीब 5.4 हजार करोड़ रुपए के हथियार बेचने को मंजूरी दी है।अमेरिकी संसद के मुताबिक सांसदों के इस समझौते पर आपत्ति जताने की संभावना नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन पार्टी, दोनों इजरायल का जबर्दस्त समर्थन करती हैं। उधर, अमेरिका के इस रवैये पर तुर्की भड़क गया है। वहां के राष्ट्रपति एर्दोगन ने बाइडेन का नाम लेते हुए कहा- 'आपने मुझे यह कहने के लिए बाध्य किया है कि आप अपने खूनी हाथों से इतिहास लिख रहे हैं।'

इजरायल-फिलिस्तीन मामले पर अरब देशों में भी संशय है। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की बैठक में इजरायल को चेतावनी दी गई कि अल अक्सा मस्जिद पर कब्जे की कोशिश की तो नतीजे भयानक होंगे। बैठक सऊदी ने बुलाई थी। पर उसने खुद अमेरिकी जेट फाइटर्स को जमीन दी है। अमेरिका इसका इस्तेमाल इजरायल की मदद में कर सकता है।द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग का खामियाजा दोनों पक्षों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी इलाके में हालात बदतर हो चुके हैं। यहां की 21 लाख की आबादी में से 11 लाख के पास पीने का पानी, टॉयलेट और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। गाजा सिटी में 7 साल पहले बिजली, पानी, सीवेज के इंतजाम थे। एक वॉटर फिल्टर प्लांट तो 2.5 लाख लोगों की प्यास बुझाता था।

केजरीवाल के दावे पर सिंगापुर का जवाब: सिंगापुर सरकार ने कहा-

हमारे यहां कोई नया वैरिएंट नहीं मिला, भारत के नेता तथ्यों पर बात करें

सिंगापुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए वैरिएंट के दावे को एक दिन बाद ही सिंगापुर सरकार ने खारिज किया है। केजरीवाल ने कहा था सिंगापुर में मिला नया वैरिएंट बच्चों के लिए खतरनाक है। सिंगापुर सरकार ने केजरी के ट्वीट का जवाब दिया और कहा- इस बात में कोई सच नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का नया वैरिएंट मिला है। हमारे देश में ज्यादातर केसों के लिए कोरोना का बी.1.617.2 स्ट्रेन ही जिम्मेदार है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं।

सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने कहा कि राजनेताओं को फैक्ट पर बात करनी चाहिए। सिंगापुर वैरिएंट जैसी कोई चीज नहीं है। इधर, भारतीय मीडिया में बीते दिन दावा किया गया था कि सिंगापुर में मिले नए वैरिएंट से भारत में तीसरी लहर का खतरा हो सकता है। सिंगापुर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि जिस वैरिएंट की वजह से देश में मामले बढ़े हैं, वो भारत में मिले वैरिएंट का एक रूप है।

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया था दावा: इससे पहले मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया वैरिएंट बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में यह तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएं। और बच्चों के लिए भी वैक्सीन विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए।

सिंगापुर में सुरक्षा को देखते हुए बंद किए स्कूल

सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने कहा कि बी.1.617.2 स्ट्रेन बच्चों पर ज्यादा असर डाल रहा है, इसकी वजह से सरकार ने प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल से स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। मिनिस्ट्री ने बताया कि जूनियर कॉलेज, प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूलों की पढ़ाई बुधवार से घर से होगी, वैसे स्कूलों में सत्र का समापन 28 मई को होना है।

सिंगापुर के शिक्षा मंत्री चान चुन सिंग ने बताया कि वायरस के नए स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हैं और ऐसा लगता है कि ये बच्चों को ज्यादा अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। यह हम सभी के लिए चिंता की बात है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि नए वायरस से संक्रमित कोई भी बच्चा गंभीर रूप से बीमार नहीं है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाए।

ब्रिटेन में न्यू नॉर्मल की शुरुआत, एयरपोर्ट पर 8-8 घंटे की वेटिंग, पब-रेस्तरां फुल

लंदन। ब्रिटेन में न्यू नॉर्मल की शुरुआत हो चुकी है। करीब पांच महीने बाद पूरा ब्रिटेन अनलॉक हो गया है। 6.76 करोड़ की आबादी वाले ब्रिटेन में ज्यादातर बार-पब, रेस्तरां और सिनेमाघर खुलने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचने भी लगे हैं। पहले दिन ब्रिटेन के ज्यादातर बार-रेस्तरां फुल रहे। इसे लेकर स्थानीय कारोबारी भी खुश हैं। उनका कहना है कि यदि सब ठीक रहा तो जल्द ही पांच महीने में हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी। पहले दिन ब्रिटेन के ज्यादातर बार-रेस्तरां फुल रहे। इसे लेकर स्थानीय कारोबारी भी खुश हैं। उनका कहना है कि यदि सब ठीक रहा तो जल्द ही पांच महीने में हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी।

दूसरी ओर, जीवन सामान्य होते ही लोगों के बीच छुट्टियां मनाने की होड़ मच गई है। ब्रिटेन के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हीथ्रो और गेटविक पर भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों को 8-10 घंटे तक कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। हीथ्रो एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारी बताते हैं- 'लोग छुट्टियां मनाने के लिए ब्रिटेन के साथ-साथ विदेशों का भी रुख कर रहे हैं। सोमवार को हीथ्रो और गेटविक एयरपोर्ट से 340 विमानों ने उड़ान भरी। इनमें से 9 रोम, 21 पेरिस और 26 न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। यूरोपीय यूनियन (ईयू) अनलॉक को लेकर अहम फैसले ले सकता है।

रूस-चीन के बीच सबसे बड़ी परमाणु डील: 2 प्रोजेक्ट की 4 यूनिट डेवलप करेंगे दोनों देश

बीजिंग। रूस और चीन के बीच नजदीकियां किस कदर बढ़ रही हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे बड़ी परमाणु डील की शुरुआत होने जा रही है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से भारत की बढ़ती नजदीकी के कारण अब चीन रूस के साथ अपने संबंध तेजी से सुधार रहा है।

बुधवार को चीन और रूस ने दो परमाणु पॉवर प्रोजेक्ट की 4 यूनिट पर ज्वॉइंट कोऑपरेशन की शुरुआत की। रूस और चीन की कंपनी इस पर मिलकर काम करेंगी। इसे चीन के 2 शहरों में शुरू किया जा रहा है।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजिअन ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्चुअली (ऑनलाइन) पॉवर प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। दोनों देशों के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर 2018 में ही सहमति बन गई थी। इसमें से एक तियानवेन परमाणु पॉवर प्लांट जिआंगसू राज्य के लिआनयूगांग शहर में है। दूसरा शुदापु परमाणु

पॉवर प्लांट लियाओनिंग राज्य के शिंगचेंग शहर में है।

इन 4 यूनिट को डेवलप करेंगे चीन-रूस

तियानवेन परमाणु पॉवर प्लांट की यूनिट 7 और 8

शुदापु परमाणु पॉवर प्लांट की यूनिट 3 और 4

दोनों देशों के बीच बढ़ेगी नजदीकी

चीनी प्रवक्ता झाओ लीजिअन ने बताया कि ये चीन और रूस के बीच अब तक का सबसे बड़ा परमाणु पॉवर प्रोजेक्ट करार है। प्रोजेक्ट के तहत पॉवर प्लांट की 4 यूनिट के लिए जरूरी उपकरण भी बनाए जाएंगे। इससे रूस और चीन की नजदीकी और बढ़ेगी। लीजिअन ने कहा है कि परमाणु प्लांट दूसरे संसाधनों के मुकाबले कार्बन का कम उत्सर्जन करते हैं। दोनों देश एक-दूसरे के साथ अपने संबंधों को दिन ब दिन मजबूत कर रहे हैं। ये एक तरह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को जवाब भी है।

नेपाल में तेज भूकंप: 5.8 की तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं

बॉर्डर से लगे बिहार के इलाकों में हो सकता है असर

काठमांडू। नेपाल में बुधवार सुबह 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है। नेपाल के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 5 बजकर 42 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र पोखरा से 35 किमी पूर्व में था। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है।

बिहार की उत्तरी सीमा पर दिख सकता है असर

नेपाल में जहां भूकंप का केंद्र है, उससे बिहार के बेतिया शहर की सीमा 300 किलोमीटर दूर है। इसलिए भूकंप का असर बिहार की उत्तरी सीमा पर भी पड़ सकता है। हालांकि, अभी तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है।

भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक, भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल होती है।

इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब शक्तिशाली भूकंप होता है।

ऐसे लगाते हैं भूकंप की तीव्रता का अंदाजा

भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उसके केंद्र (एपिसेंटर) से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस लहर से कंपन होता है। धरती में दरारें तक पड़ जाती हैं। भूकंप का केंद्र कम गहराई पर हो तो इससे बाहर निकलने वाली ऊर्जा सतह के काफी करीब होती है, जिससे बड़ी तबाही होती है।

नेपाल में बुधवार सुबह 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है। नेपाल के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 5 बजकर 42 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र पोखरा से 35 किमी पूर्व में था।

फिलीस्तीन को मदद देगा पाकिस्तान: इमरान सरकार फिलिस्तीन को मेडिकल किट्स भेजेगी; विदेश मंत्री इजराइल को रोकने की रणनीति बनाने तुर्की पहुंचे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने इजराइली हमले झेल रहे फिलीस्तीन को मदद देने का फैसला किया है। मंगलवार रात इमरान खान की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें यह तय किया गया कि पाकिस्तान सरकार कोविड संकट से घिरे फिलीस्तीनियों को मेडिकल एड यानी चिकित्सीय मदद देगी। मीटिंग के बाद इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने यह ऐलान किया। इजराइल-फिलीस्तीन की ताजा जंग में अब तक करीब 220 लोग मारे जा चुके हैं। फिलीस्तीन संगठन हमास (इजराइल इसे आतंकी संगठन बताता है) इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। जवाब में इजराइली एयरफोर्स बम बरसा रही है।

इसके पहले, पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ काफी बयानबाजी की और उससे फिलीस्तीन पर हमले रोकने को कहा। मंगलवार को ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तुर्की पहुंचे। वे यहां राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्डोगन और वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात करके इजराइल के खिलाफ रणनीति का खाका तैयार करेंगे।

कैबिनेट का फैसला

इमरान खान की कैबिनेट मीटिंग के बाद फवाद चौधरी ने मीडिया से कहा- फिलीस्तीन सिर्फ इजराइली हमलों से ही नहीं, बल्कि कोविड-19 से भी जूझ रहा है। पाकिस्तान सरकार ने उसकी मदद का फैसला किया है। हम मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें फिलीस्तीन भेज रहे हैं। कैबिनेट में इस बारे में प्रस्ताव लाया गया था। इस पर सभी की रजामंदी थी। उन्होंने कहा- फिलीस्तीन को लेकर हमारे नीति मोहम्मद अली जिन्ना के जमाने से एक ही है। मुस्लिम देश भी हमारे साथ हैं।

तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन इस मामले में जो दिल में सोचते हैं, वही हमारे प्रधानमंत्री जुबान से बोलते हैं। शुक्रवार को हम फिलीस्तीन के समर्थन में एकता दिवस मनाएंगे।

तुर्की पहुंचे कुरैशी

एक तरफ जहां मुस्लिम देशों का संगठन 'ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री'यानी OIC इस मामले पर सिर्फ बयान जारी कर रहा है, वहीं पाकिस्तान और तुर्की खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। इमरान ने विदेश मंत्री कुरैशी को तुर्की भेजा है। यहां वे कुछ और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। फिर ये सभी एक ही प्लेन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। यहां संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ एक नया प्रस्ताव लाया जाएगा।

इस बीच एक खबर अमेरिका से भी आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार रात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। हालांकि, इसका ब्योरा नहीं मिल पाया है।

इजराइल की हर हरकत पर नजर

दूसरी तरफ, इजराइल मुस्लिम देशों में चल रही तमाम गतिविधियों पर नजर रख रहा है। ओआईसी में तो सिर्फ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था और इजराइल से फौरन हमले रोकने की मांग की गई थी। वहीं, पाकिस्तान और तुर्की इस मामले में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सोमवार को ही इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि गाजा पट्टी पर हमले किसी भी सूरत में बंद नहीं किए जाएंगे कि हमास को खत्म करने के बाद ही अमन बहाली हो सकती है। दूसरी तरफ, इजराइली विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वो तमाम डिप्लोमैटिक चीजों और कार्यवाहियों पर करीबी नजर रख रहा है।

मोदी सरकार को बच्चों की जान के बजाय अपनी इमेज की चिंता : सिसोदिया

नई दिल्ली (आनंद राय) ।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कोरोना प्रबंधन को लेकर की जा रही लापरवाही की जबर्दस्त भर्त्सना की। साथ ही केंद्र पर देश में महामारी के प्रबंधन के बजाय विदेशों में अपनी इमेज चमकाने में लगे रहने और घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया।

मनीष सिसोदिया ने कहा की जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कोरोना के तीसरे लहर से बच्चों को बचाने के लिए केंद्र सरकार से अलर्ट रहने की अपील की तो केंद्र में बैठी भाजपा ने अलर्ट होने और सावधानी बरतने के बजाय घटिया राजनीति करना शुरु कर दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने दो चीजों की बात की सिंगापुर के स्ट्रेन की और बच्चों की। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा ने इसपर जो प्रतिक्रिया दी है वो साफ दिखाता है की केंद्र सरकार को भारत के बच्चों की चिंता नहीं है बल्कि सिंगापुर में अपनी इमेज बनाने की चिंता है। लेकिन केजरीवाल जी को देश के बच्चों की चिंता है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब लंदन में कोरोना का नया स्ट्रेन आया था उस दौरान भी केंद्र सरकार को डॉक्टरों और वैज्ञानिको ने आगाह किया था कि जरूरी सावधानी बरती जाए लेकिन भारत सरकार ने समय रहते कोई कदम

'तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए कब नींद से जागेगी केंद्र सरकार'

मुद्दा सिंगापुर नहीं, मुद्दा हमारे बच्चों की हिफाजत का है : मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री

नहीं उठाया और आज सारा भारत इसका खामियाजा उठा रहा है। इस दौरान भारत में हज़ारों लोगों की मौत हुई लेकिन केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। देश की हालत खराब होती रही लेकिन सरकार अलर्ट नहीं हुई और कोई कदम नहीं उठाया।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज पूरी दुनिया में जब दोबारा तीसरे लहर आने की आशंका है। पूरी दुनिया के डॉक्टर इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं, भारत में सुप्रीम कोर्ट भी लगातार आगाह कर रही है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की आँखों में बंधी पट्टी नहीं खुल रही है। केंद्र सरकार अब भी सिंगापुर को मुद्दा बनाकर अपनी इमेज बनाने में लगी है उन्हें भारत के बच्चों की कोई परवाह नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा विदेश मंत्रालय जितनी तेज़ी से केजरीवाल जी के बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए सक्रिय हुआ उतना अगर दुनिया के देशों से वैक्सीन लाने में सक्रिय हुआ होता तो आज देश में बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होती. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारत के बच्चों की जान जोखिम में डाल अपनी राजनीति करने में और विदेशों में इमेज बनाने में लगी है। पर दिल्ली सरकार को अपने बच्चों की परवाह है, हम दिल्ली के बच्चों को बचाना चाहते है।

कोरोना मृतकों के आंकड़े छिपा रही है दिल्ली सरकार : चौधरी

पीड़ित परिजनों को 50 हजार रुपए की घोषणा 'जले पर नमक छिड़कना' जैसा

पीड़ित परिवार के सदस्य लाखों रुपए पहले ही इलाज पर कर चुके हैं खर्च

नई दिल्ली (संवाददाता)।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर कोरोना मृतकों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पीड़ित परिजनों को 50 हजार रुपए देने की घोषणा 'जले पर नमक छिड़कना' जैसा है इसलिए यह राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सुभाष चोपड़ा ने बुधवार को यहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केजरीवाल सरकार की हर मृतक परिजन को 50 हजार रुपए देने की घोषणा नमक पर घाव छिड़कने की तरह है क्योंकि पीड़ित परिवार के सदस्य लाखों रुपए पहले ही इलाज पर खर्च कर चुके है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कोरोना के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को चार लाख रुपए, 50 हजार रुपए गंभीर मरीजों को तथा दस हजार रुपए पेंशन के रूप में उन परिजनों को दी जानी चाहिए जिन्होंने महामारी में अपने परिवार के कमाने वाले सदस्य को खोया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कोरोनॉ ने सभी की कमर तोड़ दी है इसलिए न्याय योजना के तर्ज पर 10 हजार रुपए हर महीनों सभी परिवारों को दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि रिक्शा चालक, मजदूरों, नाई, धोबी, मेड जैसे असंगठित मजदूरों पर इस महामारी का सबसे अधिक बुरा असर पड़ा है इसलिए उन्हें यह सहायता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अप्रेल से मई 17 के बीच 19 हजार 715 लोगों की मौत नगर निगम ने दर्ज की है, जबकि इसी दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 10 हजार 462 लोगो की मृत्यु होने का आंकड़ा दिया है, जबकि दोनों आंकड़ो के बीच जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने राज्य सरकार पर मौतों के आंकड़े को छुपाने का आरोप लगाया और कहा कि दिल्ली की जनता ने श्री केजरीवाल को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया लेकिन सरकार से उन्हें सिर्फ खोखले वादें और घोषणाएं ही मिल रही है।

संक्षिप्त खबर

कोवीशील्ड वैक्सीनेशन केंद्र 2 दिन बाद बंद होना शुरू हो जाएंगे : आतिशी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने कहा कि 18 से 44 वर्ष तक की श्रेणी के कोवीशील्ड वैक्सीनेशन केंद्र 2 दिन बाद बंद होना शुरू हो जाएंगे। कोवैक्सीन के केंद्र पहले ही बंद हो चुके हैं। दिल्ली में 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन 350 से ज्यादा स्थानों पर चल रहा है। दो दिन के भीतर कोवीशील्ड का स्टॉक खत्म होने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर अस्थाई तौर पर बंद होना शुरू हो जाएंगे। 18 से 44 वर्ष की श्रेणी के लिए केंद्र सरकार, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन मिलने की कोई जानकारी नहीं मिली है। 45 वर्ष से अधिक उम्र की श्रेणी के लिए अब 1 दिन का कोवैक्सीन और 3 दिन का कोवीशील्ड का स्टॉक बचा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कल 18 मई को 1,05,357 वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं। जिसमें से 88,332 लोगों को पहली और 17025 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है।

खुद को सिप्ला कम्पनी का कर्मचारी बताकर युवती से ठग लिए पैसे

नई दिल्ली। कोरोना से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती अपनी मां के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन ढूंढ रही एक युवती ने साइबर ठगों ने 6800 रुपए ठग लिए। आरोपी ने खुद को दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला का कर्मचारी बताया था और दो घंटे में अस्पताल में इंजेक्शन पहुंचाने की बात कह कर एडवांस पैसे लिए थे। लेकिन फिर पीड़िता का फोन नहीं उठाया, पीड़िता ने राजौरी गार्डन थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने उनकी शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शैली चोपड़ा अपने परिवार के साथ राजौरी गार्डन में रही है। गत दिनों उन्हें कोरोना हुआ था। जिसके बाद उन्हे अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान दौरान डाक्टर ने उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने के लिए कहा।

लोगों के घर तोड़ने का नोटिस भेज रही है भाजपा की एमसीडी : आप

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने बुधवार को बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा की एमसीडी लोगों के घर तोड़ने का नोटिस दे रही रही है। यह तो बहुत ही अमानवीय है। भाजपा कोरोना के समय में दिल्लीवालों की मदद या उनका बचाव तो नहीं कर पा रही है लेकिन उन्हें परेशान करने का कोई न कोई मौका ढूंढती रहती है। ऐसे समय में जब लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हैं, इस तरह से नोटिस भेजकर लोगों का घर तोड़ना ठीक नहीं है।

दिल्ली के एलजी ने की हाई लेवल मीटिंग, डी-2जी व ब्लैक फंगस की दवाएं उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

नई दिल्ली । उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को राजधानी में कोरोना से संबंधित दवा डी- 2जी व ब्लैक फंगस से संबंद्ध दवाएं मरीजों को सुगमता से ऊपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। डी- 2जी दवा डीआरडीओ द्वारा तैयार की गई है और भारी संक्रमण की स्थिति में भी कारगर है। दूसरी तरफ कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस भी फैलना शुरू हो गया है। उपराज्यपाल ने भविष्य की जरूरतों के अनुसार अस्पतालों को भी तैयार रखने का आदेश दिया व इस संबंध में विशेषज्ञों के साथ सलाह मशविरा करने का आदेश दिया। ऐसा इसलिए ताकि राजधानी के सभी अस्पताल कम मरीज होने या मरीजों की संख्या अचानक काफी ज्यादा बढने पर स्थिति से निबटने के लिए तैयार रहें।

उपराज्यपाल ने बुधवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक रखी। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्य सचिव, तीनों निगमायुक्त व दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में उपराज्यपाल ने आदेश दिया कि राजधानी के सभी दवा विक्रेता प्रतिदिन दवाओं का स्टाक व दवाओं का मूल्य दर्शाएं ताकि ब्लैक फंगस की दवा व डी 2जी मरीजों को आसानी से मिल सके।

उपराज्यपाल ने राजधानी के गरीबों को मुफ्त राशन वितरण प्रणाली की निगरानी करने का भी निर्देश दिया। साथ ही श्रमिकों को सहायता राशि जल्द निर्गत करने के लिए कहा। उन्होने कोरोना की जांच बढाने का भी निर्देश दिया। उन्होने अस्पतालों में निर्धारित समय सीमा में आक्सीजन प्लांट लगाने और प्लांट लगाने के कार्य का निगरानी करने का निर्देश भी दिया।

उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना के कम होते मामलों के बीच आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या में कोई कमी नही होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, लाकडाउन के दौरान देखा गया था कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में भी कुछ कमी आ गई थी। ऐसा बिल्कुल नही होना चाहिए।

ब्लैक फंगस के इलाज की दवा की कमी पर केंद्र व दिल्ली सरकार दे जानकारी, हाई कोर्ट ने पूछा अचानक कैसे हो गई कमी

नई दिल्ली । कोरोना महामारी से ठीक होने वाले मरीजों को अपनी चपेट में लेने वाले ब्लैक-फंगस के इलाज की दवा की कमी के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से जानकारी देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि सरकार विस्तार बताए कि आखिर समस्या है और स्थानीय स्तर पर दवा का निर्मित किये जाने के बावजूद भी इसकी अचानक आपूर्ति कम कैसे हो सकती है। राकेश मल्होत्रा ने कहा कि म्यूकोर्मिकोसिस के इलाज के लिए दवा एम्फोटेरिसिन-बी की कमी है। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने कहा कि इस दवा की कमी है और इसकी स्थिति रेमडेसिविर से भी बदतर है।

हमने केंद्र सरकार से दवा की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बनाई गई समिति दिन में दो बार बैठक् करती है, लेकिन जब स्टॉक नहीं है तो वे बफर स्टॉक नहीं दे सकते। मेहरा ने कहा कि न केवल दिल्ली बल्कि अन्य सभी राज्य इस कमी का सामना कर रहे हैं और केंद्र इन दवाओं को राज्यों को रोटेशन के आधार पर आपूर्ति करता है। पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार से कहा कि इस संबंध में निर्देश लेकर बृहस्पतिवार को जानकारी उपलब्ध कराएं। मेहरा ने स्पष्ट किया कि दवा की मांग अचानक बढ़ गई है और बीते चार दिन से इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार म्यूकोर्मिकोसिस या ब्लैक फंगस एक संक्रमण के कारण होने वाली जटिलता है। इस बीमारी का पता उन रोगियों में लग रहा है जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं या ठीक हो चुके हैं।

दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था ने केजरीवाल की नाकामी को उजागर दिया : गुप्ता

अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश करती रही केजरीवाल सरकार

(एजेंसी)

नई दिल्ली। कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली में भयावह स्थिति बनी हुई है उसके लिये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं। ये आरोप दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लगाए।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की कुप्रशासन और अक्षमता के कारण दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर झूठ बोलकर मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके मंत्री दिल्लीवासियों को गुमराह करते रहे जिसके कारण लोगों ने अपनों को खो दिया। दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की नाकामी को उजागर कर दिया, लेकिन जिम्मेदारी से बचने की कोशिश में केजरीवाल सरकार अपनी लापरवाही का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश करती रही। कितनी शर्म की बात है कि जिस वक्त दिल्ली की जनता को केजरीवाल और उनकी पार्टी की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग दिल्ली की जनता को लूट रहे थे, उनकी जान की कीमत लगा रहे थे और ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे। खुद को दिल्ली का बेटा कहने वाले केजरीवाल ने महामारी से जूझ रही दिल्ली को उसके हाल पर ही छोड़ दिया। प्रदेश कार्यालय में बुधवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी और सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया।

दिल्ली में 44 दिन बाद कोरोना संक्रमण दर 6 फीसदी से कम

24 घंटे में 3846 नए मामले, 235 की मौत

(एजेंसी)

नई दिल्ली । दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। 5 अप्रैल के बाद दिल्ली में 6 फीसदी से कम संक्रमण दर दर्ज की गई। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को 3846 नए मामले सामने आए। वहीं 9427 मरीजों को छुट्टी दी गई, जबकि 235 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। दिल्ली में अभी तक 1406719 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1339326 मरीज इनमें से ठीक हो चुके हैं। वहीं

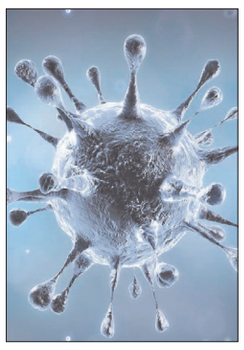

22346 मरीज कोरोना के कारण दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मृत्युदर बढ़कर 1.59 फीसदी हो गई है। विभाग के अनुसार दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 45047 हैं। इनमें से दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में 13368 मरीज भर्ती हैं। वहीं कोविड केयर सेंटर में 618 और कोविड मेडिकल सेंटर में 103 मरीज हैं।

होम आइसोलेशन में 27112 मरीज भर्ती हैं। विभाग के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को 66573 टेस्ट हुए जिसमें 5.78 फीसदी मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। इन जांच के लिए आरटीपीसीआर से 46785 और रैपिड एंटीजन से 19788 टेस्ट हुए। दिल्ली में अभी तक 18474059 टेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या 56732 हो गई है।

ब्लैक फंगस का इलाज घर में संभव नहीं, उपचार की दवाएं अस्पतालों को सीधे मिलेः सत्येंद्र जैन

नई दिल्ली । दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने वैक्सीनेशन पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि दिल्ली में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है और कोवीशील्ड की करीब दो दिन की बची है। केंद्र सरकार से अभी तक वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन हमें जल्द वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरी कंपनियों से फार्मूला साझा करते हैं, तो बड़े पैमाने पर वैक्सीन बना सकते हैं। भारत के पास रोजाना एक करोड़ वैक्सीन उत्पादन की क्षमता है। दिल्ली में संक्रमण दर घट कर अब 6.89 फीसद पहुंच गई है। हम जल्द से जल्द इसे 2 फीसद से नीचे लाना चाहते हैं और दिल्ली को कोरोना मुक्त कराना हमारा आखिरी लक्ष्य है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में करीब 27 हजार बेड में से 13 हजार

बेड खाली हैं। आईसीयू के साढ़े छह हजार बेड़ में से 1200 बेड खाली हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में करोना के मामले ना आएं। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस का उपचार तय नियमों के मुताबिक किया जाता है। इसका पहले भी उपचार हो रहा था। ब्लैक फंगस का इलाज घर पर नहीं हो सकता है। ऐसे में कोशिश करेंगे कि उपचार की दवाएं अस्पतालों को सीधे मिलें। दवाइयों का पहले उत्पादन कम था। अब हमने दवाइयों की मांग की है कि हमें अधिक संख्या में इनकी डोज दी जाएं। हमने अभी एक लाख दवाओं की मांग की है।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस कर दिल्ली में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर कहा कि दिल्ली में कल (18) मई को कोरोना के 4482 मामले आए थे और संक्रमण दर 6.89 फीसद रही है। दिल्ली के अंदर 24 अप्रैल के बाद से मामले धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। दिल्ली में पहले कोरोना के मामले 1 दिन में 28 हजार तक आ रहे थे, जो अब छह हजार से नीचे होते-होते चार हजार के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरना की संक्रमण दर को 2 फीसदी से कम पर लाने का लक्ष्य है। दिल्ली में जब अचानक केस बढ़े थे, तब संक्रमण दर एक से दो फीसदी के आसपास चल रही थी। इसके बाद संक्रमण दर अचानक बढ़कर 36 फीसदी तक पहुंच गई थी। दिल्ली में अब हालात पहले से बेहतर हैं। पांच फीसदी से अधिक संक्रमण दर को काफी खराब माना जाता है। अभी संक्रमण दर 6 फीसदी के आसपास है। दिल्ली सरकार का आखिरी लक्ष्य है कि दिल्ली में कोरोना का कोई भी मामला ना रहे। कोविड - 19 के मामले जल्द से जल्द जीरो हो जाएं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बड़ों के साथ बच्चों को बचाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को सीधे दवा उपलब्ध कराने के लिए हमने एक लाख दवाओं की मांग की है।

नई दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोविड केयर सेंटर में कोविड -19 से स्वस्थ होने के बाद एक बुजुर्ग महिला बाहर आती हुई।

किन्नरों को भी लगे टीका, दिल्ली-एनसीआर में अलग से कैंप लगाने की मांग

नई दिल्ली/नोएडा । कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता और टीकाकरण ही सबसे आवश्यक है। किन्नर समाज को भी टीका लगवाने के लिए अब तक किसी सामाजिक संस्था या सरकार ने पहल नहीं की है। वहीं, दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर में किन्नर समाज के लोगों और सामाजिक संगठनों ने मंगलवार को जिलाधिकारी को पत्र लिख कर इनके लिए अलग से टीकाकरण केंद्र बनाने की मांग की है। उन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किन्नरों के लिए अलग से टीकाकरण शिविर लगाने की अपील की है।

इस बाबत उरूज हुसैन का कहना है कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा के साथ दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवन और सोनीपत में हजारों की संख्या में किन्नर रहते हैं। ज्यादा लोग इनके प्रति जागरूक नहीं हैं, इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पाते और जो लोग मुश्किल से पता कर वहां जाते भी हैं तो अधिकतर किन्नर को देखकर कुछ असुविधा महसूस करते हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि उनके लिए अलग से केंद्र बनाए जाएं, ताकि वह भी टीकाकरण अभियान का हिस्सा बन सकें। उरूज बताती हैं कि जिले में करीब दो हजार किन्नर होंगे। एनजीओ की मदद से वह अबतक जिला अस्पताल में 20 लोगों को ही टीका लगवा पाए हैं। जरूरी है कि दिल्ली के साथ इससे सटे शहरों में किन्नरों के

लिए अलग से कैंप लगाकर कोरोना का टीका लगवाया जाएगा। उधर, जेपी अस्पताल के हड्डी रोग और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. संजय गुप्ता के कहा कि आज टीकाकरण हमारा सबसे बड़ा रक्षक है और जन-जन टीकाकरण अभियान समय की मांग है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की विभिन्न वैक्सीन ने 70 से 80 फीसद प्रभावी होने का प्रमाण दिए हैं। लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि वैक्सीन संक्रमण होने से तो नहीं बचा सकती लेकिन मध्यम या गंभीर बीमारी के नुकसान और अस्पताल में भर्ती होने से बचा सकती है। टीकाकरण के संक्रमण के जो मामले सामने आए हैं, उनमें प्रभाव हल्का दिखा और वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों में मृत्यु दर के मामले कम सामने आए हैं। इसलिए सभी को वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए।

संपादकीय

मदद और मंशा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राजनेताओं को जरूरी दवाओं की जमाखोरी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर वे जनता की मदद करना चाहते हैं, तो दवाओं को केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को सौंप सकते हैं, ताकि सरकारी अस्पतालों में उनका इस्तेमाल हो सके। पूर्वी दिल्ली से सांसद और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर ने यह घोषणा की थी कि एंटीवायरल दवा फेविपिरावियर या फैबिफ्लू उनके कार्यालय में उपलब्ध है और लोग वहां से मेडिकल परची दिखाकर इसे ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि वह दवा जब्त कर ली गई है और उसे सीजीएचएस को सौंप दिया जाएगा। ऐसे और भी उदाहरण हैं। गुजरात भाजपा अध्यक्ष ने यह घोषणा की थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सूरत में पार्टी कार्यालय में मिल सकता है। उनके विरुद्ध भी मामला गुजरात हाईकोर्ट में उठा है। महाराष्ट्र में भी कई नेताओं पर आरोप लगे कि उन्होंने रेमडेसिविर अपने रसूख से हासिल किए और बांटे। दरअसल, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोरोना संक्रमण में बहुत मांग है और देश भर से इसे पाने के लिए मारामारी की खबरें आ रही थीं। इसी वजह से केंद्र सरकार ने इसका वितरण अपने हाथों में ले लिया और यह तय किया कि इसे सिर्फ सरकारी तंत्र के जरिये ही बेचा जाएगा।

यह राजनेताओं की जिम्मेदारी होती है कि वे मुसीबत में लोगों की यथासंभव मदद करें और तमाम नेता कमोबेश ऐसा करते भी हैं। कुछ नेता तो सचमुच मन से और पूरी ताकत से मददगार बनने की कोशिश करते हैं, कुछ काम कम करते हैं, और प्रचार ज्यादा करते हैं। इस महामारी के दौर में भी तमाम राजनेता अपने-अपने तरीके से मदद कर रहे हैं या मददगार दिखने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि महामारी के जोर से व्यवस्था चरमराई हुई है, संसाधनों की कमी है, इसलिए समर्थ लोगों से मदद की दरकार भी ज्यादा है। कई मददगार लोगों की कहानियां इस वक्त लोगों की जुबान पर हैं और समाज में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी है। पर यही बात उन लोगों के बारे में नहीं कही जा सकती, जो दुर्लभ दवाएं बांटकर मददगार होना या दिखना चाह रहे हैं। अगर उनमें से कुछ की नीयत भली भी रही हो, तब भी उनका तरीका गलत था। जैसे, गौतम गंभीर की आलोचना होती रही कि जब दिल्ली में कोरोना का कहर जोरों पर था, तब वह आईपीएल में कमेंट्री करने में व्यस्त थे। फिर अचानक उन्होंने फैबिफ्लू बांटने का फैसला किया। यह वायरस-रोधी दवा है, पर कोरोना में इसके इस्तेमाल का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, न ही किसी मान्य चिकित्सा संगठन ने कोरोना में इसके इस्तेमाल को सही ठहराया है। ऐसी दवा को बांटने से मरीजों का कुछ भला नहीं होना था, और यह कानूनन भी सही नहीं था। इसके बजाय गौतम गंभीर किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेकर उस पैसे को अन्य काम में लगाते, तो हर तरह से बेहतर होता। रेमडेसिविर के निजी वितरण पर सरकार जब रोक लगा चुकी थी, तब तो नेताओं को इसे बांटकर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। ज्यादा अच्छा यह होता कि वे अपने रसूख का इस्तेमाल रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ाने और उसका वितरण व्यवस्थित करवाने के लिए लगाते। मदद करने के और भी तरीके हैं। जो सबसे चमकीला हो, वह अक्सर सबसे अच्छा नहीं होता।

सीमाओं से ऊपर उठें

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार की कोविड-19 नीति के विरुद्ध राजधानी दिल्ली में लगाए गए पोस्टर के मामले में दिल्ली पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिस पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में ऐसे करीब 1800 पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर लिखा था-मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया! इनकी गिरफ्तारी आईपीसी की धारा 188 के तहत की गई थी। हालांकि इनमें से अधिकांश को अदालत से जमानत मिल गई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये पोस्टर किस व्यक्ति विशेष के आदेश पर या किसी राजनीतिक दल के कहने पर छपे हैं। यह वास्तविकता है कि कोरोना महामारी को लेकर केंद्र और राज्य, दोनों ही सरकारों की ओर से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन विदेशों में वैक्सीन भेजने को लेकर किसी तरह की आलोचना नहीं होनी चाहिए और न ही सियासत होनी चाहिए। भारत में वैक्सीन के निर्माण के बाद सरकार ने वैक्सीन मैत्री के माध्यम से विकासशील और विकसित देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की। मांग की तुलना में वैक्सीन की मात्रा कम थी लेकिन इससे भारत ने बहुत सद्भावना अर्जित की। उस समय भारत में संक्रमण काबू में था और उसमें कमी के संकेत थे। विदेशों में वैक्सीन भेजना भारत की एक अच्छी पहल थी। इस बात पर सभी भारतीयों को गर्व करना चाहिए कि जब अमीर देशों ने स्वार्थी रुख अपनाया तब भारत ने कोरोना संकट का सामना करने के लिए विश्व समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन किया। शुरू में कोरोना से निपटने के लिए उपयोगी माने जाने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी दवा भी भारत ने दुनिया के अनेक देशों को भेजी थी। भारत के विपक्षी नेताओं को यह समझना चाहिए कि कोरोना महामारी का एक सार्थक संदेश यह हो सकता है कि सीमाओं के आरपार फैलने वाले संकट का मुकाबला भी सीमाओं के ऊपर उठकर करना होगा। यदि इस संदेश पर अमल हो तो गरीब देश इस महामारी की दोहरी मार से बच सकते हैं। लेकिन पोस्टर विवाद के मामले का एक अन्य पहलू यह भी है कि पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं उन्हें जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त कर सकता है या उसे प्रचारित कर सकता है।

प्रवीण कुमार सिंह

खुलेंगी खिड़कियां एक दिन

सन 1947 में भारत का विभाजन एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें सहमतियों से अधिक असहमतियों की गुंजाइश हमेशा बची रहती है। बहुत सारे मिथक हैं, जो हमने अपने नायकों, घटनाओं व नतीजों के इर्द-गिर्द बुन रखे हैं, और जैसे ही कोई बौद्धिक इन्हें 'डीकंस्ट्रक्ट' करने का प्रयास करता है, उसे बहुत से पूर्वाग्रहों और सरलीकृत स्थापनाओं से जूझना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान, दोनों जगहों पर विभाजन को लेकर एक ऐसा विमर्श मौजूद है, जिसके केंद्र में हिंदुओं और मुसलमानों के 1,300 वर्षों से अधिक के संग-साथ की तल्खियां और मिठास दिख ही जाती है। दोनों देशों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास की पाठ्य पुस्तकें खुद ही एक गंभीर समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय हो सकती हैं। किसी एक ही शख्सियत या घटना के बारे में दोनों के विवरणों और स्थापनाओं में इतना अंतर दिखता है कि विश्वास नहीं होता, वे एक ही विषय-वस्तु के इर्द-गिर्द अपना ताना-बाना बुन रहे हैं।

इस तरह की विभक्त बौद्धिक दुनिया में पिछले कुछ वर्षों से प्रोफेसर इश्तियाक अहमद एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कर रहे हैं। लाहौर में जन्मे, पले-बढ़े और शुरुआती शिक्षा प्राप्त पाकिस्तानी मूल के स्वीडिश नागरिक प्रो अहमद वहीं इतिहास और राजनीति शास्त्र पढ़ाते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अंग्रेजी में छपी उनकी दो पुस्तकें पंजाबः लहूलुहान, विभाजित और नस्ली सफाई तथा जिन्ना : सफलताएं, असफलताएं और इतिहास में उनकी भूमिका भारतीय उपमहाद्वीप की सांप्रदायिक राजनीति को समझने का प्रयास करने वाले किसी भी गंभीर अध्येता के लिए अनिवार्य पाठ्य सामग्री बन गई हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए 1,300 वर्षों के उस पड़ोस को समझना जरूरी है, जो आठवीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय के साथ शुरू हुआ था। यह पड़ोस दुनिया की दो बड़ी जीवन पद्धतियों का था। एक तरफ, धर्म की शास्त्रीय समझ से परे हिंदू थे और दूसरी तरफ, आसमानी किताब और आखिरी पैगंबर में यकीन रखने वाले मुसलमान और स्वाभाविक ही इनकी विश्व दृष्टि एक-दूसरे से बहुत भिन्न थी। इस संग-साथ ने रचनात्मकता की दुनिया में बहुत कुछ श्रेष्ठ निर्मित किया। साहित्य, संगीत, स्थापत्य, मूर्तिकला, पाक शास्त्र- हर क्षेत्र में इन्होंने मिल-जुलकर अद्भुत योगदान किया। पर यह कहना सरलीकरण होगा कि दुनिया के दो बड़े धर्मों के अनुयायी सिर्फ रचनात्मक लेन-देन कर रहे थे, सही बात यह है कि वे हजार साल से अधिक एक-दूसरे से लड़ते भी रहे थे। इसी तरह के दूसरे सरलीकरण हैं कि लड़ते तो सिर्फ शासक थे, प्रजा प्रेम से रहती थी या हिंदुओं और मुसलमानों को ब्रिटिश शासकों ने लड़ाया, अन्यथा वे तो शांति से रहना चाहते थे। विभाजन को लेकर भी सरलीकृत धारणाएं हैं, जो भारतीय समाज के सांप्रदायिक रिश्तों को समझने की कोशिश करने वाले मुझ जैसे जिज्ञासु को उलझन में डालती रही हैं। इन्हीं कुछ गुत्थियों को सुलझाने का मुझे मौका मिला, जब पिछले दिनों मैंने प्रो इश्तियाक से एक लंबी बातचीत की। सभी जानते हैं, विभाजन ने एक करोड़ से भी अधिक परिवारों को प्रभावित किया था। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए या मारे गए। विभाजन में तो मुख्य रूप से पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था और

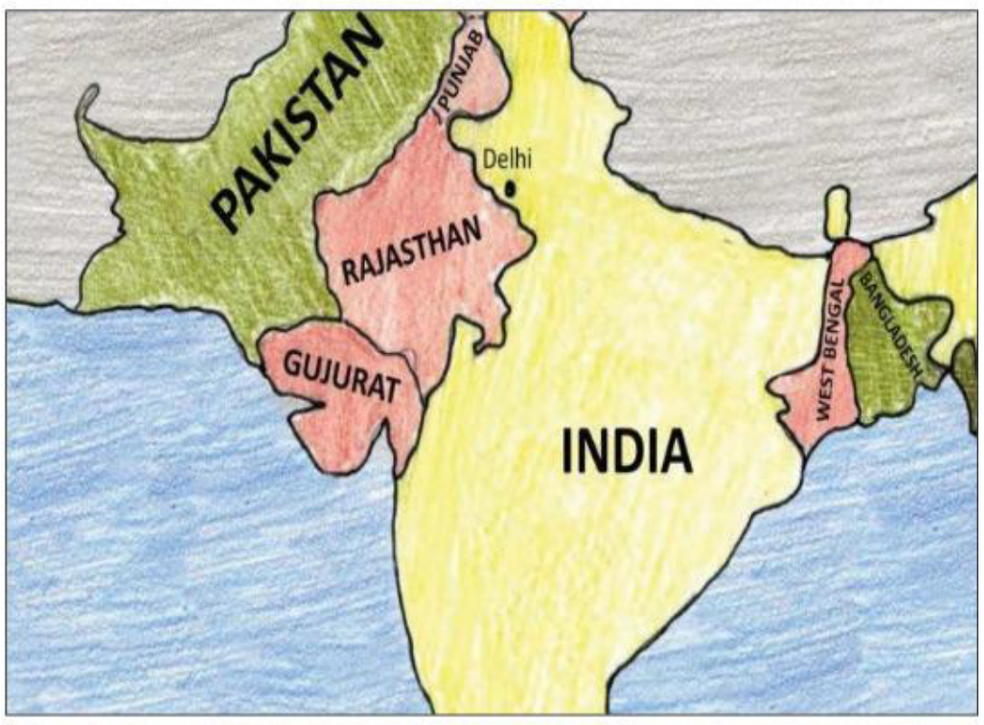

प्रो इश्तियाक ने पंजाब पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। दोनों तरफ के दर्जनों विस्थापितों से इंटरव्यू लेकर उन्होंने मौखिक इतिहास का दुर्लभ व मूल्यवान दस्तावेजीकरण किया है।

भारत में बहुत से लोग, जिनमें फैजान मुस्तफा जैसे आधुनिक और असदुद्दीन ओवैसी जैसे कट्टरपंथी शरीक हैं, तर्क देते हैं कि हिन्दुस्तान के मुसलमान अपनी मर्जी से भारतीय हैं। उन्हें 1947 में मौका मिला था कि वे पाकिस्तान जा सकते थे, पर वे अपनी धरती से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने भारत नहीं छोड़ा। मुझे इस स्थापना से हमेशा दिक्कत होती है कि क्या पाकिस्तान से आने वाले सिख और हिंदू अपनी धरती से प्यार नहीं करते थे। इस स्थापना से आजाद भारत के गांधी-नेहरू जैसे रोशन ख्याल नेतृत्व के प्रयासों का अपमान होता है, जिनके कारण भारत से उस तरह से मुसलमानों की नस्ली सफाई नहीं हो सकी, जैसे पाकिस्तान से सिखों और हिंदुओं की हुई। उन्होंने अपनी पंजाब वाली किताब का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने विस्तार से मार्च 1947 में रावलपिंडी में सिखों पर मुसलमानों के हमलों का जिक्र किया है। इसमें कई हजार सिख मारे गए थे और हजारों परिवार उजड़कर पटियाला पहुंचे थे। यह आजादी के पहले की शुरुआती नस्ली सफाई थी। बाद में शेष पाकिस्तान में इसी पैटर्न की दूसरी कार्रवाइयां हुईं और नतीजतन आज एक प्रतिशत से कम हिंदू, सिख वहां हैं। इसके बरक्स भारत में क्या हुआ? मार्च में जब सिख भागकर आए, तब जरूर नस्ली सफाई का एक दौर आया, जिसमें सिखों ने मुसलमानों को मलेरकोटला छोड़कर पूरे पंजाब से खदेड़ दिया। याद रहे कि तब का पंजाब दिल्ली की सीमा तक था। पर जब तक नस्ली सफाई का सिलसिला दिल्ली तक पहुंचा, देश आजाद हो चुका था और बलवाइयों के लिए गांधी और नेहरू एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए। गांधी तो सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध अनशन पर बैठ गए और इसे तोड़ने के लिए उनकी एक शर्त यह भी थी कि हिंदू और सिख बलात कब्जा की गई अन्य संपत्तियों के साथ मस्जिदों को भी मुसलमानों को वापस सौंप दें। इस तरह का कोई प्रयास जिन्ना या लियाकत अली खां द्वारा पाकिस्तान में नहीं किया गया। भारत में आजादी के बाद के रोशन ख्याल नेतृत्व को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने नस्ली सफाई नहीं होने दी और अधिसंख्य मुसलमान देश में रुक सके। इसी तरह, कैबिनेट मिशन को लेकर एक मिथ यह है कि यदि कांग्रेस ने उसे मान लिया होता, तो विभाजन टल सकता था। पर प्रो इश्तियाक से बात करके यह मिथ टूटता है। वह मानते हैं कि कैबिनेट मिशन की असफलता का मुख्य कारण जिन्ना की हठधर्मिता ही अधिक थी। प्रो इश्तियाक भारत-पाकिस्तान के उन बुद्धिजीवियों में हैं, जो विश्वास करते हैं कि यद्यपि सन 1947 के पहले की स्थितियां लौटाई नहीं जा सकतीं, पर यूरोपीय यूनियन जैसी व्यवस्था तो हो ही सकती है, जिसमें वीजा खत्म हो सकता है, व्यापार निर्बाध हो जाए या साहित्य और संस्कृति की खिड़कियां खोलकर ताजी हवा के झोंके आने दिए जाएं। हम दोनों ने इसी उम्मीद के साथ बातचीत खत्म की कि हमारे जीवन में ही यह दिन आएगा जरूर।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

> "भारत में आजादी के बाद के रोशन ख्याल नेतृत्व को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने नस्ली सफाई नहीं होने दी"

न्यायिक व्यवस्था भी गहरे तक प्रभावित

पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली कोविड-19 वैश्विक महामारी ने चिकित्सा सुविधाओं से लेकर पुलिस प्रशासन और आम नागरिकों को अपने अदृश्य दंश से अछूता नहीं छोड़ा है। देश की न्यायपालिका भी इसका अपवाद नहीं रही। इस महामारी की वजह से शीर्ष अदालत से लेकर निचली अदालतों और न्यायिक अधिकरणों का काम बुरी तरह प्रभावित रहा। न्यायपालिका ने आवश्यक मुकदमों की वीडियो कानफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की और जनता को अनेक मामलों में राहत देने का प्रयास किया, परंतु इसके बावजूद लंबित मुकदमों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है।

न्यायालय ने हालांकि कोरोना संक्रमण के दौरान सीमित संख्या में मुकदमों की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिये शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण विवाद पर अपना फैसला सुना दिया है। यह दीगर बात है कि केन्द्र सरकार ने इस फैसले के एक हिस्से पर न्यायालय से पुनर्विचार का अनुरोध किया है।

शीर्ष अदालत के तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी यहां नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिकता, अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को खत्म करने की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ ही धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश, मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और दाऊदी समुदाय में महिलाओं का खतना करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई कारगर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकी।

शीर्ष अदालत के साथ ही उच्च न्यायालयों ने कोरोना काल के दौरान कामगारों के पलायन से उत्पन्न स्थिति और इस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के अनेक राज्यों में ऑक्सीजन और दवाओं के संकट का स्वतः संज्ञान लिया और केन्द्र तथा राज्य सरकारों को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह किया।

न्यायपालिका की इस सक्रियता के बावजूद कोरोना काल से प्रभावित वकीलों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अपने राज्यों के बार संगठनों से आर्थिक मदद की गुहार भी की है। इन संगठनों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। दूसरी ओर, कोरोना के कहर ने न्यायपालिका का सामान्य कामकाज प्रभावित किया है। इस स्थिति से निपटने के लिये हालांकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने ऑनलाइन फाइलिंग व्यवस्था शुरू की लेकिन देश के सभी अधिवक्ताओं के लिये इस सुविधा का लाभ उठा पाना संभव नहीं है।

फिलहाल इस संकट का अंत नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि उच्चतम न्यायालय से लेकर निचली अदालतों तक में लंबित मुकदमों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और न्यायपालिका को न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए युद्धस्तर पर सक्रिय होना पड़ेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय देश की अदालतों में 4,43,24,488 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें उच्चतम न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या 67,898 और उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या 58,05,006 है जबकि निचली अदालतों में 3,84,51,584 मुकदमे लंबित हैं। इसी तरह, न्यायपालिका में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। शीर्ष अदालत और सरकार के बीच न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित ज्ञापन को लेकर चल रही खींचातानी का नतीजा है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत 34 पदों में से सात और उच्च न्यायालयों में स्वीकृत 1080 पदों में से 420 पद रिक्त हैं। इसी तरह, अधीनस्थ अदालतों में स्वीकृत 24,247 पदों में से अभी भी 4,928 पद रिक्त हैं। यह स्थिति न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों तथा अदालत के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमण से प्रभावित होने की वजह से ज्यादा गंभीर हो गयी है।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने हाल ही में यह जानकारी दी है कि कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के कारण उच्च न्यायालयों के कम से कम तीन न्यायाधीश और 34 न्यायिक अधिकारियों की मृत्यु हो चुकी है। इस दौरान उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश एमएम शांतनागौदर का भी निधन हो गया। यही नहीं, कोरोना काल में उच्च न्यायालयों के 106 न्यायाधीश, 2768 न्यायिक अधिकारी और उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के करीब 800 कर्मचारी भी इस संक्रमण के शिकार हुए। इनमें न्यायालय के कम से कम छह रजिस्ट्रार और 10 अतिरिक्त रजिस्ट्रार भी शामिल रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ भी तमाम सावधानियों के बावजूद इसकी चपेट में आ गये।

उम्मीद की जानी चाहिए कि देश को कोरोना महामारी से जल्द ही मुक्ति मिलेगी और केन्द्र तथा राज्य सरकारें जनता को शीघ्र न्याय दिलाने के लिये न्यायपालिका में रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्तियां करेंगी।

परिधि/राजीव मंडल

टेंडर में ऑक्सीजन

एक बहुत ही, मतलब परम से भी परम घुटे हुए नौकरशाह के पास बैठा हुआ था, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। मैंने कहा-वहां कोरोना से इतने लोग मर गए। आप कर क्या कर रहे हैं। नौशा उर्फ नौकरशाह ने बताया-आप तथ्यों को सही कीजिए। इतने लोग ऑक्सीजन ना मिलने से मरे, इतने लोग कोरोना के बाद की कमजोरी से मरेग कोरोना से कोई ना मरा। कोरोना प्रबंधन एकैदम ठीक है। इस पर मैंने थोड़ा नाराज होकर कहा-हद है, कोरोना से ना मरेग तो कैसे मर गए। तो नौशा ने बताया-हर साल लू से मरते हैं, डेंगू से मरते हैं। इस बार कोरोना का फैशन हैग लोग बता रहे हैं कि कोरोना से मर रहे हैं। पर मर वो दरअसल लू और डेंगू से रहे हैं। और लू और डेंगू से मरना तो नॉर्मल है, तो इसमें शोर मचाने की क्या बात है। मैंने कहा-आप कहते हैं कि शोर मचाने की क्या बात है, ऑक्सीजन नहीं है अस्पतालों में। नौशा ने कहा-अब आप तथ्य सही रख रहे हैं। लोग कोरोना से नहीं, ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। तो हमने सचिव को लिख दिया है, सचिव ने विशेष सचिव को लिख दिया है, विशेष सचिव ने प्रमुख सचिव को लिख दिया है। प्रमुख सचिव ने टेंडर निकाल दिए हैं। टेंडर ग्लोबल अखबारों में छप गए हैं। मैंने कहा-कमाल है, ऑक्सीजन मरीज को चाहिए अस्पताल में और आप टेंडर में ऑक्सीजन दे रहे हैं। नौशा-देखिए, ऑक्सीजन है, टेंडर में है। मतलब ऑक्सीजन गायब नहीं है। परेशान ना हों। मैंने कहा-आप क्यों परेशान होंगे, आप टॉप क्लास अफसर हैं। आपको तो कहीं भी किसी भी अस्पताल में दाखिला मिल जाएगा। नौशा-जी तो आप भी बन जाइए, टॉप क्लास अफसर। किसने रोका है किसी को टॉप क्लास अफसर बनने से या टॉप क्लास मंत्री बनने से। पब्लिक अगर सिर्फ पब्लिक ही बनी रह जाएगी, तो यह उसकी चाइस है, हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र में सबको मौके हैं, कोई कुछ भी बन सकता है, मंत्री से लुटेरा तक, अफसर से लेकर छिछोरा तक। पब्लिक नहीं बन पाई मंत्री तो गलती पब्लिक की है। तो समझ में आ गया है कि गलती पब्लिक की ही है।

मजदूर, भूख और उनकी व्यथा

धनंजय राय

उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के मनियर क्षेत्र निवासी सुरेन्द्र पिछले 2020 के लॉकडाउन में बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गांव पहुंचे थे। बताते हैं कि उस समय मैंने तय कर लिया कि कुछ धंधा-पानी करके गांव में ही गुजारा कर लूंगा लेकिन शहर नहीं जाऊंगा। सुरेन्द्र ने सूद पर पैसे लेकर नवम्बर में गांव में किराना की दुकान खोल ली। उनके बाद शहर से लौटे दो और लोगों ने किराना की दुकान खोल ली। गांव में पहले से भी दो दुकानें हैं। तकरीबन 250 की आबादी वाले पूर्वे में 5 दुकानें हो गई हैं। ऐसे में मंद बिक्री का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऊपर से गांव में भी ऑनलाइन खरीदारी होने लगी है। दुकानदारी की स्थिति बहुत खराब है। मूल पूंजी ही खा रहे हैं। दो बच्चों के पिता सुरेन्द्र बताते हैं कि कोरोना की पहली मार का घाव भरा भी नहीं था कि दूसरे प्रहार से आतथक तंगी के कारण दो भाइयों में बंटवारा भी हो गया। बाबूजी को कैंसर है।

अलग-अलग शहरों में मजदूरी का कार्य करते रहे बांसडीह क्षेत्र के विनोद पिछले लॉकडाउन में घर आ गए थे। सोचा था कि गांव में ही मेहनत-मजदूरी कर लूंगा लेकिन वापस शहर नहीं जाऊंगा। विनोद यहां भी मायूस हैं। बताते हैं कि अब तो खेती में भी मजदूरों का कोई खास काम नहीं रहा। मशीनों के चलते अब काम नहीं मिलता। मनरेगा से थोड़ी उम्मीद थी लेकिन पंचायत चुनाव के कारण वहां भी निराश हुए। कोटे की दुकान से कुछ महीने अनाज की मदद तो मिली लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण पिछले कुछ महीनों से वो भी बंद है। विनोद कहते हैं कि महामारी से बच गए तो फिर शहर जाएंगे नहीं तो भूखों मर जाएंगे। रानी शहर के ही एक मोहल्ले में घरों में चौका-बासन कर दो बच्चों तथा बीमार पति का भरण-पोषण करती हैं। कोरोना की पिछली लहर से ही उनका काम बंद है। पति की दवा बंद हो गई। कर्ज का बोझ बढ़ गया। गहने बिक गए। परिवार खाने को मोहताज हो गया। दिसम्बर में जैसे-तैसे दो घरों में मेट का काम मिला था। परिवार के खाने का बंदोबस्त होने लगा। तब तक कोरोना की दूसरी लहर ने फिर तोड़ दिया।

शहर, कस्बा और गांव हर जगह मजदूरों की स्थिति कमोबेश एक जैसी है। यह तस्वीर स्पष्ट बयां करती है कि कोरोना के खिलाफ जंग की गंभीरता, सबके लिए एक जैसी तो है, लेकिन इससे लड़ने वाले लोग दो प्रकार के हैं। एक वो जो सिर्फ और सिर्फ कोरोना से लड़ रहे हैग और दूसरे वो लोग हैं जो कोरोना के साथ-साथ भूख से भी लड़ रहे हैं। इनमें असंगठित क्षेत्र के भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों इत्यादि की स्थिति सबसे चिंताजनक है। कोरोना की लड़ाई तो फिर भी संक्रमण के बाद की लड़ाई है, भूख से तो हर प्रहर और हर दिन लड़ना पड़ता है। ऐसे में विमर्श का विषय केवल यह नहीं है कि कोरोना की दूसरी लहर में भूख से लड़ाई का स्वरूप कितना भयावह है? बल्कि न्यायसंगत विमर्श तो तब होगा जब हम देख पाएं कि मजदूर भूख की लड़ाई खाली पेट और भरी जिम्मेदारियों के साथ विगत 14 महीने से लड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि टूटते रिश्तेग बढ़ती चिंताग सरकारी और सामाजिक अनदेखी को झेलते हुए घटते वजन और ढ़ीली पड़ती मांसपेशियों के सहारे यह वर्ग कोरोना और भूख की दोहरी जंग को भाग्य भरोसे कब तक झेल पाएगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016 की बात करें तो इसके तहत किसी भी खतरे को कम करने के लिए तय किए गए प्रमुख कार्यक्षेत्रों में 'क्षमता विकास तथा पुनर्वास' प्रमुख कार्य हैं। मतलब साफ है कि आपदा के समय सरकार को राहत कार्यों के साथ-साथ क्षमता विकास और पुनर्वास का कार्यक्रम भी समानांतर रूप से चलाना चाहिए। देखा जाए तो सरकार राहत के आलावा, आपदा के अन्य पक्षों पर शून्य सी है। आलम यह है कि आम आदमी अपने क्षमता विकास की योजना खुद बना रहा हैग और गिरते-पड़ते भाग्य भरोसे चल रहा है। ऐसे में नितांत आवश्यक है कि सरकार तथा नीति-नियामक संस्थाएं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आम जन के क्षमता विकास तथा पुनर्वास के लिए रोडमैप तैयार करें।

इस कार्य में केंद्र, राज्य तथा गांव, सरकार सहित सभी हितभागी संस्थाओं की भूमिका का निर्धारण भी अत्यंत महद्मवपूर्ण है। ध्यान रहे कि कोरोना अकेले आया है लेकिन भुखमरी का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि यह जिस भी समाज में जाती है, अपने साथ-साथ चोरी, हत्याग लूट सबको ले जाती है। और ये सब मिलकर किसी बनी-बनाई व्यवस्था को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91
से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

भिंड: शादी में पहुंचे 200 से ज्यादा लोग, मामला दर्ज

भिंड। ऊमरी क्षेत्र में 200 मेहमान शादी में शामिल होने आ गए लेकिन पुलिस ने उन्हें सजा के तौर पर बीच सड़क पर मेंढक चाल में चलवाया। पुलिस ने दूल्हे समेत टैंट मालिक पर एफआईआर दर्ज की है। आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास में बुधवार को शादी समारोह का आयोजन चल रहा था। दूल्हे की लगुन फलदान उत्सव समारोह के लिए करीब 500 से ज्यादा लोगों को बुलावा भेजा था। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो करीब 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस को देखकर कई लोग मौके से भाग निकलेए तो कइयों को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया। बमेहमानों से मेंढक चाल चलवाने की सजा दी गई। इस दौरान कई युवकों से कान पकड़कर उठक-बैठक लगवाई। यहां पुलिस ने 250 से अधिक के लोगों का भोजन फिंकवाया।

जबलपुर: शादी से इंकार किया तो खूनी संघर्ष, एक की मौत

जबलपुर। जिले में एक युवती के शादी करने से इंकार के बाद नाराज युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर आतंक मचाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पनागर थाना क्षेत्र के राम बचौड़ा में काजल नामक युवती से जबलपुर निवासी अनुज पटेल शादी करना चाहता था। युवती ने शादी से इंकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर मंगलवार को अनुज अपने साथियों के साथ युवती के घर के सामने आकर गालीगलौज करने लगे। इस बीच कुंजीलाल पाठक ने विरोध किया तो सभी ने मिलकर धारदार हथियार व डंडे और चाकू से उन पर हमला कर दिया। इसके साथ ही युवती के भाई विवेक के साथ मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुंजीलाल की मौत हो गई।

श्योपुर: निजी संस्था के कर्मी से 3.91 लाख की लूट

श्योपुर। बुधवार शाम 05 बजे श्योपुर-शिवपुरी हाइवे स्थित कलमी गांव के पास तीन बदमाशों ने निजी संस्था के कर्मचारी को जंगल में बंधक बनाकर उसके पास से नकदी,मोबाइल व पर्स लूटकर ले गए। जानकारी के अनुसार शिवपुरी जिले के छर्च निवासी 25 वर्षीय युवक जयपुर में नव जागृति संस्था में कार्यरत है । युवक बाइक से किसी को पेमेंट देने श्योपुर आ रहा था। तभी कलमी-ककरधा के बीच युवक की बाइक पंचर हो गई जिसे लेकर युवक पैदल ही जा रहा था तभी एक बाइक पर सवार तीन बदमाश उसे पकड़कर जंगल में ले गए और उसकी मारपीट की। युवक की शर्ट उतारकर उसके हाथ पीछे कर बांध दिया। बदमाश युवक से बैग जिसमें 3 लाख 91 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल व पर्स लूटकर ले गए।

इंदौर: लॉकडाउन में कराई बेटे की शादी, एसआई अटैच

इंदौर। एरोड्रम थाने के सब इंस्पेक्टर को लॉकडाऊन में बेटे की शादी धूमधाम से करना महंगी पड़ गई। सब इंस्पेक्टर को सजा बतौर थाने से हटाकर लाइन अटैच कर दिया, वहीं एसआई और उसके समधी पर केस भी दर्ज किया है। एरोड्रम थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर राजेश गौड़ के बेटे आकाश की 4 दिन पहले शादी थी। राजेश गौड़ क्षेत्र के ही शिक्षक नगर में रहते हैं। शादी में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। बैंड बाजा बारात निकली। अधिकारियों को अब इस शादी के बारे में पता लगा तो राजेश गौड़ से शादी की परमिशन मांगी गई जो उसके पास नहीं निकली। एसपी महेशचंद जैन ने राजेश गौड़ को थाने से हटाकर लाइन अटैच कर दिया। वहीं थाने में उनके खिलाफ 188 का केस भी दर्ज हुआ है। मामले में एरोड्रम टीआई पर भी गाज गिर सकती है।

धमतरी: छग के 88 गांव में अब तक नहीं पहुंचा कोरोना

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर यह है कि अब तक जिले के 88 गांव में कोरोना का संक्रमण पहुंच नहीं पाया है। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक जिले के सभी चार विकासखंडों में से सिर्फ कुरुद ब्लाक इससे बच नहीं पाया। तीन विकासखंड धमतरी, मगरलोड एवं नगरी क्षेत्र के 88 गांव में कोरोना का संक्रमण नहीं पहुंचा है जबकि कुरुद विकासखंड के 135 गांव इससे अछूता नहीं रहे। धमतरी ब्लॉक के 148 गांव में से फिलहाल 21 गांव कोरोना से पूरी तरह मुक्त है। मगरलोड ब्लाक के 166 गांव में से 11 गांव में कोरोना नहीं पहुंच सका। इसी तरह नगरी ब्लॉक के 224 गांव में से सर्वाधिक 56 गांव में कोरोना वायरस काफी दूर है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 146 की मौत, 5680 नए मरीज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 5680 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं 146 संक्रमितों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 5680 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं उनमें सर्वाधिक रायगढ़ के 441 हैं। इसमें कोरिया के 419, जांजगीर के 363, कोरबा के 387, रायपुर के 309, बिलासपुर के 204, दुर्ग के 154, राजनांदगांव के 112, बलौदा बाजार के 317, बेमेतरा के 101, महासमुन्द के 133, कबीरधाम के 86, धमतरी के 128,सरगुजा के 275, जशपुर के 306, गरियाबन्द के 107, कांकेर के 136, सूरजपुर के 436,मुंगेली के 225, बालोद के 116 तथा बस्तर के 168 मरीज शामिल हैं।

कोरोना मामले में सरकार को हाईकोर्ट की दो टूक, लूट की न हो छूट

ब्लैक फंगस एवं तीसरी लहर की तैयारी सहित अन्य बिंदुओं पर मांगा जवाब

जबलपुर (एजेंसी)।

मप्र हाईकोर्ट ने बुधवार को कोरोना संबंधी मामलों में निजी अस्पताल द्वारा रेट लिस्ट चस्पा न होने व खुली लूट होने संबंधी आरोप को काफी गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस मो. रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधरन की स्पेशल बेंच ने मामले तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि लूट की छूट न हो। इसके साथ ही न्यायालय ने निजी अस्पतालों को श्रेणी के आधार पर विभक्त कर उनके उपचार दर के निर्धारण संबंध में सुझाव मांगे है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस व कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी पर भी सरकार से जवाब मांगा है, जिसकी फिलहाल प्रतीक्षा है।

याचिका पर अगली सुनवाई 24 मई को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट में बुधवार को कोरोना संबंधित आधा दर्जन याचिकाओं की सुनवाई दौरान न्यायालय को बताया गया कि सरकार द्वारा सितम्बर 2020 में आदेश जारी कर कहा गया था कोविड उपचार के नाम पर निजी अस्पताल फरवरी 2020 को निर्धारित अपनी दर से सिर्फ 40 प्रतिशत अधिक राशि ले सकते हैं। निजी अस्पतालों द्वारा मई 2021 में अपनी रेट लिस्ट सरकार को सौंपी गई। सरकार के पास निजी अस्पतालों की फरवरी 2020 की कोई निर्धारित लिस्ट उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि प्रत्येक तीन माह में निजी अस्पताल अपने निर्धारित दरों की जानकारी सीएचएमओ को उपलब्ध कराए। युगलपीठ को बताया गया कि एक ही श्रेणी अगल-अगल अस्पतालों की रेट अलग-अलग हैं।

इंजेक्शन के मनमाने दाम पर साक्ष्य समेत मांगा शपथपत्र

हस्तक्षेप याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि निजी अस्पताल रेमडेसिविर इंजेक्शन के मनमाने दाम वसूल रहे है, जो कि इंजेक्शन उन्हें 12 सौ से 13 सौ मिल रहा है, उसके 5 से 6 हजार तक के दाम वसूले जा रहे है। जिस पर सरकार की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई कि यदि ऐसा है तो उसके साक्ष्य पेश किये जाए, जिस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जिस पर न्यायालय ने हस्तक्षेपकर्ता को साक्ष्य सहित शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं।

वेंटिलेटर के संबंध में पेश करो जानकारी

कोर्ट मित्र की ओर से युगलपीठ को बताया गया कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से प्राप्त हुए 100 वेंटिलेटर का उपयोग तक नहीं किया गया। इसके अलावा कई जिलों में वेंटिलेटर खराब पड़े हुए है। युगलपीठ ने सरकार को निर्देशित किया है कि पीएम रिलिफ फंड से प्राप्त वेंटिलेटर तथा जिलों में उपलब्ध प्रयोग में आने वाले एव बंद वेंटिलेटर के संबंध में जानकारी पेश करें।

थर्ड बेव तथा ब्लैक फंगस के संबंध में क्या तैयारी?

न्यायालय को बताया गया कि हालही में दिल्ली में आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा बताया गया था कि 31 जिलों में आईसीयू बेड की सुविधा तक नहीं है। विश्लेषकों के अनुसार इसी वर्ष कोरोना की तीसरी वेव आने वाली है तथा ब्लैक फंगस को प्रकोप भी बढ़ रहा है। इस संबंध में सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों के संबंध में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश युगलपीठ ने जारी किए हैं।

वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर संबंधी मामले में जवाब-तलब

मामले में दायर एक याचिका में मांग की गई थी कि प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया जाये। वैक्सीनेशन के संबंध में प्रदेश सरकार की अपनी कोई नीति नहीं है और पूरी तरह से केन्द्र सरकार पर निर्भर है। युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए मामले में नोटिस जारी कर सरकार को स्ट्रंक्शन प्राप्त कर पक्ष रखने के निर्देश दिये है।

प्रतिबंधित अस्पतालों का सरकार करे संचालन

मामले की सुनवाई दौरान केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि अनियमित्ताओं के कारण प्रशासन द्वारा कई निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के एडमिड करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन अस्पतालों में आईसीयू बेड व वेटिलेटर आदि उपलब्ध है। इसके अलावा बडी संख्या में बेड भी उपलब्ध है। इस अस्पतालों का संचालन सरकार द्वारा किया जा चाहिए। इस सुझाव पर युगलपीठ ने सरकार से जवाब मांगा है।

जब्त इंजेक्शनों का हो प्रयोग

वहीं एक आवेदन में कहा गया कि पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में जप्त किये गये रेमडेसिविर इंजेक्शनों का प्रयोग किये जाने के निर्देश दिये जाये, क्योकि उन पर एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद वह किसी काम के नहीं होंगे। जिस पर न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि संबंधित थानों की कोर्ट के समक्ष आवेदन कर सही इंजेक्शन है उनको प्रयोग में लिया जाये। मामले में बतौर कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, अधिवक्ता जुबीन प्रसाद, सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने पक्ष रखा।

खरगोन की बलकवाड़ा पुलिस ने कालाबाजारी करते पांच को दबोचा

कर्मचारी ही अस्पताल से हेराफेरी कर 25000 में बेचते थे इंजेक्शन

12 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त

खरगोन, (एजेंसी)। जिले के बलकवाड़ा थाना पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में इंदौर स्थित दो अस्पतालों के कर्मचारियों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि शुक्ला अस्पताल इंदौर में कार्यरत मुख्य आरोपी दिलीप पाटीदार, सीएचएल अस्पताल इंदौर में कार्यरत ओटी टेक्नीशियन रोहित पाटीदार, सचिन शितोले निवासी ठीकरी, अभिषेक कनासे निवासी जुलवानिया थाना तथा हर्ष महाजन निवासी ठीकरी को गिरफ्तार कर उनसे विभिन्न कंपनियों के 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किये गए। उन्हें बुधवार को खरगोन स्थित एक न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से 3 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि दिलीप पाटीदार अस्पताल से इंजेक्शन की हेराफेरी कर उसे रोहित पाटीदार को देता था जो इन्हें 25000 रुपए में शेष तीनों आरोपियों को बेचने के लिये दे देते थे। दिलीप पाटीदार डॉक्टर नहीं है, किंतु मेडिकल प्रैक्टिस करता है। बलकवाड़ा के थाना प्रभारी वरुण तिवारी ने बताया कि तीनों आरोपियों ने धार, बड़वानी, इंदौर तथा खरगोन जिलों में 20 से अधिक इंजेक्शन बेचे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से इंजेक्शन को लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है। संभावना है कि यह इंजेक्शन नकली भी हो सकते हैं।

चार आरोपियों को सूरत से इंदौर लाई पुलिस

इंदौर। शहर में 1200 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने चार आरोपियों को पुलिस बुधवार को सूरत से इंदौर लेकर आई। पुलिस ने इन चारों आरोपियों के साथ इंदौर से पकड़े गए अन्य चार सहित आठ आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। मुख्य आरोपी सुनील मिश्रा ने इंदौर में 700 इंजेक्शन दो दिन में बेचने की बात कही थी। विजयनगर पुलिस बुधवार को सूरत से आरोपी सुनील मिश्रा, कुलदीप, पुनीत शाह और कौशल वोरा को लेकर इंदौर पहुंची। कौशल वोरा, पुनीत शाह और कुलदीप ने मोरबी में किराए के फार्म हाउस में ग्लूकोज व नमक से नकली इंजेक्शन बनाए थे। सुनील मिश्रा निवासी रीवा ने इंदौर में ये नकली इंजेक्शन बेचे थे। विजय नगर पुलिस की सूचना पर सूरत पुलिस को इस पूरे रैकेट को पकड़ा था। इस गिरोह के अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

पुलिस ने बरामद की खाली शीशियां, मोखा की पत्नी और मैनेजर से पूछताछ जारी

जबलपुर। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खपाने के मामले के आरोपी सरबजीत सिंह मोखा की मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती जा रहीं है। पुलिस आरोपी मोखा की पत्नि जसमीत व अस्पताल की मैनेजर सोनिया खत्री शुक्ला से लगातार पूछताछ कर रहीं है, जो कि 20 मई तक की पुलिस रिमाण्ड में है। वहीं आरोपी मोखा का पुत्र हरकरण विगत कई दिनों से भूमिगत है तो वहीं अस्पताल के एक कर्मी दीपक कुशवाहा रहस्मय ढंग से गायब हो गया है, जिसकी शिकायत दीपक की पत्नि ने गोरखपुर थाने में दर्ज कराई है। बीते दिवस जहां एसआईटी ने मोखा की पत्नि जसमीत और मैनेजर सोनिया को रिमाण्ड में लेकर सघन पूछताछ की, जिसमें नकली इंजेक्शन के साक्ष्य छिपाने में दोनों की भूमिका पायी गई, इतना ही नहीं सूत्रों की माने तो पुलिस ने दोनों के पास से दो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किये है। पुलिस जसमीत और मोखा की रजदार सोनिया से लगातार पूछताछ कर रहीं है।

सतना जिले में बिजली गिरने की तीन घटनाओं में सात लोगों की मौत, तीन अन्य झुलसे

बारिश-तूफान से बचने मंदिर के पीछे छिपे, गिरी गाज

सतना, (एजेंसी)। जिले में बिजली के गिरने की तीन अलग-अलग घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार पहली घटना मैहर-बदेरा थाना क्षेत्र में हुई जहां आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। इस घटना में तीन अन्य लोग भी घायल हुए है।

बताया गया कि यह सभी लोग मछली पकड़ने के लिए गये थे। वह सतना, कटनी और शहडोल जिले की सीमा से लगे धर्मपुरा पुरानी बस्ती के पास नदी मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान दोपहर करीब तीन बजे आंधी-तूफान और बारिश आई। बचने के लिए सभी लोग हनुमान मंदिर के पीछे छिप गए। यहां बिजली गिर गई। सभी लोग झुलस गए। आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस के मुताबिक अविनाश, जितेंद्र कोल, सुरेन्द्र साहू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं भरत कोल ने इलाज शुरू करने से पहले ही दम तोड़ दिया। वहीं, राजू कोल, सिपाही कोल और संपत कोल को अस्पताल में भर्ती किया गया है।

इसी तरह दूसरी घटना में मझगवां थाना क्षेत्र के कैलाशपुर में बारिश के कारण पेड़ के नीचे खड़े दो ग्रामीण बिजली गिरने से उसकी चपेट में आ गए। इस घटना में दोनों लोगों की मौत हो गई। हादसे में सतीशचंद्र पांडे निवासी कोठी व उमेश कुमार मिश्रा के रूप में हुई है। इसके अलावा रामनगर थाना क्षेत्र में छोटेलाल साकेत निवासी डागा की हुई आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। हादसा रामनगर से हरई रोड पर हुआ। राह चलते युवक पर बिजली गिरने की आशंका है।

एक बच्चे की मौत, दो घायल

छतरपुर। बमीठा थाना क्षेत्र के ग्राम किशोरगंज में बीती शाम करीब 5 बजे भग्गू का 16 वर्षीय पुत्र राहुल, उसका भांजा कृष्णा और 4 वर्षीय रवि पुत्र खमेचंद्र अहिरवार घर में खेल रहे थे तभी बारिश के साथ आकाशीय बिजली घर पर आ गिरी। बिजली गिरने से राहुल की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कृष्णा और रवि गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं भग्गू और उसकी पत्नी को मामूली धमक लगी है।

50 भेड़-बकरियों की मौत

टीकमगढ़। जिले में बिजली गिरने से चार दर्जन से अधिक भेड़ बकरियों की मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों से तेज आंधी के साथ बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से ग्राम रायपुर के पशुपालक किसान जगदीश के पालतू 50 भेड़ और बकरियों की मौत हो गई। पुलिस ने प्रकरण जांच में ले लिया है।

कोयला खदान हादसे में एक कर्मी की मौत

बैतूल। जिले के सारणी थाना क्षेत्र के पाथाखेड़ा में वेस्टन कोल फील्ड (वेकोलि) कोयला खदान में बुधवार को हुए हादसे में एक कर्मी की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वेकोलि की तवा टू खदान में दोपहर में सपोर्ट निकालने के दौरान रामचरण चेतिया (59) गंभीर घायल हो गया। उसे तत्काल वेकोलि के एरिया अस्पताल पाथाखेड़ा लाया जहाँ डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद वेकोलि अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

यूनेस्को की प्राकृतिक श्रेणी में मप्र के दो स्थल

सतपुड़ा और भेड़ाघाट विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल

होशंगाबाद, (एजेंसी)। सतपुड़ा टाईगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ाघाट-लम्हेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है।

प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि अब मध्यप्रदेश ऐसा राज्य बन गया है, जहां से दो स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहरों की प्राकृतिक श्रेणी की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अगले चरण में इन स्थलों का नॉमिनेशन डॉजियर यूनेस्को द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि संभावित स्थलों की सूची में विशिष्ट विशेषताओं वाले स्थलों को ही शामिल किया जाता है। शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने सतपुड़ा टाईगर रिजर्व एवं भेड़ाघाट-लम्हेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहरों की संभावित सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव डायरेक्टर जनरल एएसआई, भारत सरकार को 9 अप्रैल 2021 को प्रेषित किया था। एएसआई यूनेस्को को उक्त प्रस्ताव प्रेषित करने के लिये नोडल विभाग है।

श्री शुक्ला ने बताया कि इस उपलब्धि में मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड, वन विभाग और वाइल्ड लाइफ इन्स्टीट्यूट देहरादून का विशेष योगदान रहा। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने मध्यप्रदेश में संभावित स्थलों की पहचान एवं उनकी विशेषताओं के आधार पर उत्कृष्ट स्थलों के चयन का कार्य देहरादून स्थित डब्ल्यूआईआई केटेगरी-2 सेन्टर को सौंपा था। लगभग एक वर्ष में एनालाइसिस और फील्ड वर्क के दौरान ऐसे स्थलों की पहचान की गई तथा तथ्यों के अन्वेषण के साथ तीन महत्वपूर्ण कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। पहली कार्यशाला भोपाल में, दूसरी कार्यशाला ऋषिकेश में और तीसरी कार्यशाला पचमढ़ी में आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में पर्यटन एवं वन विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ वन, पर्यटन एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी सम्मिलित हुए।

प्रदेश में कोरोना से 88 लोगों की मौत पांच हजार से अधिक मरीज मिले

एक्टिव केस के हिसाब से प्रदेश 15वें नंबर पर आया

भोपाल, (एजेंसी)। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दिनों दिन घटते मामले के बीच बुधवार को भी राज्य भर में पांच हजार से अधिक कोरोना के नए मरीज मिले है। इस महामारी ने आज 88 लोगों की जान ले ली। प्रदेश की कोरोना पॉजिटिविटी दर जो 1 मई को 20.3 प्रतिशत थी, जो 19 मई को घटकर 6.96 प्रतिशत हो गई है। एक्टिव केसेस की संख्या के हिसाब से मध्यप्रदेश 21 अप्रैल को देश में 7वें नंबर पर था। बुधवार को स्थिति में बेहतर सुधार के साथ प्रदेश 15वें नंबर पर आ गया है।

राज्य के स्वास्थ्य संचालनालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर 72,756 लोगों की जांच की गई। जांच सैंपल रिपोर्ट में 5,065 लोग कोरोना संक्रमित पाये गये हैं। वहीं 67691 की जांच सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव रहे और बाकी रिजेक्ट किए गए। पॉजीटिविटी रेट (संक्रमण दर) 6.9 प्रतिशत दर्ज की गई। इस महामारी से मुक्त होकर राज्य में 10,337 लोग घर रवाना हुए हैं। वहीं प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 77,607 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने अब तक 7,47,783 लोगों अपनी गिरफ्त में लिया है। हालांकि इनमें से 6,6949 लोगों ने संक्रमण को मात देकर घर पहुंच गए हैं। इस महामारी ने अब तक प्रदेश में 7227 लोगों की जान ले चुका है। बुधवार को 88 लोगों की मौत हुई है।

राज्य के इंदौर जिले में बुधवार को 1153 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं दूसरे स्थान पर भोपाल जिले में 653 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा ग्वालियर में 105, जबलपुर में 324, उज्जैन में 151, रतलाम में 160, रीवा में 175, सागर जिले में 198 नए कोरोना मरीज मिले है। बाकी अन्य जिलों में भी 7 से लेकर 100 के बीच कोरोना संक्रमित मिले है।

वैक्सीन के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कराने के नाम पर ठगी

लिंक ओपन की करते ही खाते से उड़े 38 हजार

ग्वालियर। एक युवक के मोबाइल कॉल आया और पूछा कि ऑनलाइन स्लॉट बुक कराया क्या। जब युवक ने बताया कि ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं हो रहा तो कॉल करने वाले ने लिंक भेज दी। जैसे ही युवक ने लिंक ओपन की उसके खाते से 38 हजार रुपए कट गए। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर की है। घटना का पता चलते ही पीड़ित साइबर सेल पहुंचा और मामले की शिकायत की। साइबर सेल ने पीड़ित का शिकायती आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर निवासी राम कुमार धाकड़ प्राइवेट जॉब करते हैं। दो दिन पहले उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने वैक्सीन की लगने की जानकारी ली। जब उसने बताया कि उसे अभी वैक्सीन नहीं लगी है तो कॉल करने वाले ने ऑनलाइन स्लॉट बुक कराने की कहा और उससे आधार कार्ड सहित अन्य जानकारी लेने के बाद एक लिंक उसके मोबाइल पर भेजी। जैसे ही रामकुमार ने लिंक ओपन की, उसके कुछ ही समय बाद उसके मोबाइल पर रुपए निकलने का मैसेज आया। उस नंबर पर कॉल किया तो नंबर बंद मिला, इसी बीच उसके खाते से 38 हजार रुपए निकल गए। ठगी का पता चलते ही वह साइबर सेल पहुंचा और मामले की शिकायत की।

समाजसेवा

निगमायुक्त ने मानव धर्म निभाते हुए मिसाल कायम की

अस्थियां लेने नहीं पहुंचा कोई, ननि कर्मियों ने की विसर्जित

सागर, (एजेंसी)। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा काकागंज मुक्तिधाम में 20 कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया गया उसके पश्चात जब कोई उनके परिजन अस्थियां संचय करने नहीं आये तो नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार ने मानव धर्म निभाते हुए निगम के कर्मचारियों द्वारा हिन्दू रीति रिवाज से अस्थियों का संचय कराया गया और पूरे विधि विधान से बरमान घाट मां नर्मदा नदी में इन अस्थियों का विसर्जन कराया।

कोरोना संक्रमण के डर से परिजन इन अस्थियों को उठाने नहीं आये थे जिसकी सूचना निगमायुक्त को मिली तो उन्होने निगम कर्मचारियों से इन अस्थियों का संचय कराया और उन्हें बरमान घाट में ले जाकर विधि विधान से विसर्जन करने के निर्देश दिए जिन्हें मंगलवार सुबह काकागंज श्मशानघाट से निगम कर्मचारियों की टीम जिसमें प्रमुख रूप से प्रभारी अधिकारी प्रहलाद रैकवार, कुलदीप बाल्मीकि, आशुतोष सोलंकी, रंजीत साहू, अजय रैकवार, राकेश खटीक एवं उनकी टीम के 10 कर्मचारी सुबह वाहन से बरमान घाट रवाना हुए और वहां नर्मदा नदी में अस्थियों

का विसर्जन कर इनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। यह कार्य मानव सेवा की दिशा में मिसाल है।

नर्मदा में अंतिम संस्कार पर प्रतिबंध

सिवनी मालवा। ग्राम पंचायत भिलाड़िया और बाबरी में नर्मदा नदी में अंतिम संस्कार किए जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ग्राम भिलाड़िया के सचिव मोनू यादव ने बताया कि नर्मदा नदी प्रदूषित न हो इसको लेकर यह निर्णय लिया है कि अंतिम संस्कार न नर्मदा में न करते हुए मुक्तिधाम में ही अंतिम संस्कार करें।

समूह की महिलाओं ने 24 हजार से अधिक मास्क बनाए

इंदौर। कोरोना काल में आई चुनौतियों से निपटने में ग्रामीण महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। इंदौर जिले के सांवेर विकासखंड के ग्राम मेलकलमा की श्री गणेश स्व-सहायता समूह की सदस्यों

द्वारा पिछले वर्ष आई कोरोना महामारी के समय से ही मास्क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की देख-रेख में चल रहा है। समूह सदस्यों द्वारा इस वर्ष करीब 6 हजार मास्क जनपद पंचायत सांवेर को निर्माण कर उपलब्ध करवाए गए। सांवेर जनपद के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रबंधक विजय पांचाल ने बताया कि यह मास्क 10 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से जनपद को दिए गए हैं। निर्माण स्थल से भी 10 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से क्रय किया जा सकता है। इस कार्य में तकरीबन 30 महिलाएं जुड़ी हैं। श्री विजय पांचाल ने बताया कि पिछले वर्ष भी समूह ने कोरोना की आपदा आने के बाद 18 हजार मास्क का निर्माण किया था। समूह की महिलाएं अब तक कुल मिला कर 24 हजार मास्क का निर्माण कर चुकी हैं।

टूलकिट मामले में रमन एवं पात्रा के खिलाफ दर्ज करवाई प्राथमिकी

रायपुर, (एजेंसी)। टूलकिट विवाद में छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बुधवार को कांग्रेस के कूटरचित लेटरहेड की झूठी और मनगढ़त कहानी सोशल मीडिया में प्रचारित करने के आरोप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

लेटरहेड की झूठी कहानी सोशल मीडिया में प्रचारित करने का आरोप

राजधानी के सिविल लाइंस थाने में एनएसयूआई अध्यक्ष आकाश शर्मा के आवेदन पर डॉ. सिंह, पात्रा एवं सोशल मीडिया पर इसे शेयर करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 504, 505(1) क. ख. 469 एवं 188 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बुधवार को यहां जारी बयान में इस बीच कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी ब्लाकों में संबंधित थानों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संबित पात्रा तथा बीएल संतोष के खिलाफ कांग्रेस के जाली लेटरहेड में फर्जी एवं मनगढ़त फेक न्यूज साझा कर देश में साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज करवाया है।

संक्षिप्त खबर

कलचुरी सेना परिवार के सहयोग से 40 जरूरतमंद परिवारों को दिया 1 माह का राशन

भोपाल। वरिष्ठ नागरिक मंच कलार समाज मप्र द्वारा कोरोना कॉल में समाज के 40 जरुरतमंद परिवारों को एक माह की राशन की किट का वितरण किया गया। मंच की अध्यक्षा कल्पना आईडी राय ने बताया कि राशन की किट कलचुरी सेना परिवार के सदस्यों कौशल राय, संजय चौकसे, प्रमोद राय, जीतू रायए लक्ष्मी नारायण चौकसे, प्रमोद ओम जायसवाल, दीपक राय, राजेश राय ने जरुरतमंद परिवारों को घर-घर जाकर पहुंचाई। उन्होने बताया कि वरिष्ठ नागरिक मंच कलार समाज 75 परिवारों को राशन की किट उपलब्ध करायेगा पहले चरण में मंगलवार को 40 परिवारों को राशन की किट पहुंचाई गई। समाज के गरीब एवं जरुरत मंद परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए मंच की अध्यक्ष कल्पना रायए प्रकाश मालवीय,, आईडी राय, जीएन वर्मा, आरपी मालवीय इत्यादि सहयोग कर रहे है। मंच के सुरेश मालवीय, डीपी गुप्ता, नीता रायए पीडी राय, सतीश आर्य, बालमुकुंद चौकसे, कमलेश राय, विष्णु जायसवाल, भगत सिंह मालवीय, सीताराम चौधरी, डॉ मालती पटेल, शोभा हनुमान मालवीय, हरीश मालवीय, शोभा भिसे ऐसे परिवारों से संपर्क कर रहे है जिन्हें राशन की आवश्यकता है और उन्हें परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कतों का समाना करना पड़ रहा है।

स्वर्णकार समाज का महारक्त दान शिविर रविवार को

भोपाल। मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में रविवार 23 मई को प्रातः 11.30 बजे से एक दिवसीय महा रक्तदान शिविर का आयोजन प्राचीन मंदिर श्री बांके बिहारी, 50, मारवाड़ी रोड, भोपाल में आयोजित किया गया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा सोनी ने बताया कि कोरोना काल के चलते सभी हॉस्पिटलों में खून की भारी कमी आ गई है, अता कोरोना के अलावा जो ऑपरेशन हो रहे है जिनमें नियमित रक्त लगता है उन सभी रक्त बैंक में खून की भारी कमी को देखते हुए स्वर्णकार समाज ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है जिसमें श्री क्षत्रिय स्वर्णकार समाज एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशेष योगदान रहेगा। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है कृपया वे रक्तदान नहीं करें। कार्यक्रम को सुव्यवस्थित एवं शासन प्रशासन की निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सफलतम आयोजन करने हेतु, मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष नितिन सोनी एवं जिला अध्यक्ष धीरज सोनी को मनोनीत किया गया हे, इनकी देखरेख में पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। रक्तदान शिविर में स्वर्णकार समाज के अलावा भी इच्छुक लोग रक्तदान कर सकते हैं।

निगम अमले ने विभिन्न क्षेत्रों से हटाये अनेक अतिक्रमण

भोपाल। नगर निगम द्वारा सड़कों, फुटपाथों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण कर आवागमन को बाधित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर की जा रही है। निगम अमले ने सीएम हेल्प लाइन की शिकायत के निवारण के लिए लेडी अस्पताल के पास अवैध रूप से निर्मित 02 चबूतरों को तोड़ा। निगम अमले ने उद्घोषणा के माध्यम से लालघाटी चौराहे से 03 ठेले, जबकि कमलापार्क, रोशनपुरा, जहांगीराबाद, लेडी हास्पिटल, अल्पना तिराहा, बस स्टैण्ड, घोड़ा नक्कास, मंगलवारा, इतवारा, बुधवारा, एमएलबी कॉलेज तक 20 ठेले तथा रॉयल मार्केट स्टेट बैंक, कलेक्टर आफिस, बैरागढ़, गांधी नगर, गोंडीपुरा, दाता कालोनी, पंचवटी तक सब्जी एवं फलों के 29 ठेलों के अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की। निगम अमले ने करोंद, पीपुल्स, अयोध्या बायपास, आलम नगर, आनंद नगर, पिपलानी, सोनागिरी, जेके रोड, आईटीआई तक 20 ठेले जबकि स्टेट बैंक, पीरगेट से 05 ठेले तथा शाहजहांनाबाद, पुतलीघर, डीआईजी बंगला, आरिफ नगर से 12 ठेलों के अतिक्रमणों को हटाकर 04 कांटे जप्त किये।

गुजरात में तूफान टाक्टे से भारी नुकसान, विजय रूपाणी करेंगे हवाई निरीक्षण

अहमदाबाद । चक्रवात टाक्े टे के गुजर जाने के बाद अब गुजरात व दीव में तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 45 हो गया, वहीं खेती व फलों के बागों को भारी नुकसान हुआ है। 30 लाख टन नमक भी पानी में बह गया, वहीं पर्यटन स्थल दीव भी उजाड़ नजर आने लगा है। मुख्े यमंत्री विजय रूपाणी ने मृतकों को चार-चार लाख व घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता की घोषणा की है। वे गुरुवार को सौराष्ट्र के प्रभावित जिलों का हवाई निरीक्षण करेंगे। गुजरात सरकार ने चक्रवात प्रभावित जिले भावनगर, गीर सोमनाथ, अमरेली व जूनागढ सहित सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात में युद्ध स्तर पर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है। सौराष्ट्र के 125 बस डिपो से एक हजार बसों का संचालन शुरू किया गया है। 9685 गांवों में से करीब छह हजार में बिजली सुविधा बहाल कर दी गई है। प्रभावित क्षेत्रों के बाधित 959 राष्ट्रीय व राज्यमार्ग पर आवागमन शुरु कर हो गया है।

45 की मौत, 28 हजार घर उजडे

राजस्व विभाग की मानें तो राज्े य में डेढ़ लाख हेक्े टेयर में फसल बर्बाद हुई है। आम, नारियल, चीकू के पेड़ व मूंगफली, कपास, बाजरा व गेहूं की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। इंडियन साल्ट मेन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अनुसार, गुजरात में 30 लाख टन नमक खराब हो गया है। गुजरात में चक्रवात से 45 की मौत हो चुकी है, 50 हजार वृक्ष उखड़ने व 28 हजार घर व झोपड़े नष्ट होने का अनुमान है। मंगलवार का दिन अहमदाबाद के लिए भी उथल पुथल भरा रहा। 50 से 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने जहां कई घर व झोपड़े उजाड़ दिए, वहीं 200 से अधिक वृक्ष उखड़ गए। 24 घंटे में छह इंच बारिश दर्ज की गई। बुधवार शाम को जमालपुर, ढालघरवाड काजी का धाबा के पास बनी एक पांच मंजिला इमारत अचानक गिर गई। एक दिन पहले ही यहां रहने वालों परिवार इसे खाली करके कहीं अन्यत्र चले गए थे। जमीन में नमी के कारण यह ताश के पत्ते की तरह ढह गई।

लापता नहीं हुए गीर के शेर

गीर जंगल से 18 एशियाई शेरों के चक्रवात में लापता होने की बात को वन विभाग ने अफवाह बताया है। मुख्े य वनसंरक्षण अधिकारी वसंत वसावडा ने बताया कि गीर जंगल में सभी शेर सुरक्षित हैं तथा वन विभाग उनकी लगातार निगरानी कर रहा है। चक्रवात के कारण शेरों को कोई नुकसान नहीं हुआ तथा ना ही शेर लापता हुए हैं।

पीएम मोदी ने घोषित किया राहत पैकेज - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से प्रभावित गुजरात के विविध जिलों के लिए 1000 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है। साथ ही, चक्रवात के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर आए थे। उन्होंने भावनगर, जूनागढ़, अमरेली तथा सोमनाथ जिले का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद भावनगर से सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष प्रधान सचिव के कैलाशनाथन मुख्य सचिव अनिल मुकीम राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव डॉ जयंती रवि आदि अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन किया। चक्रवात से प्रभावित लोगों को राहत व पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपये का पैकेज की घोषणा की। मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता करेगी। केंद्र सरकार की ओर से घायलों को भी 50 - 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, ऑक्सीजन परिवहन के लिए टैंकर उपलब्ध कराने पर विचार करे

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसे प्रदेश को ऑक्सीजन परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में टैंकर उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि प्रदेश के भीतर या पास के ऑक्सीजन प्लांट से राज्य सरकार को ऑक्सीजन का आवंटन किया जाए, जिससे उसके परिजन में समय बर्बाद नहीं हो। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर दिए। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए हम विश्वास करते हैं कि केंद्र सरकार दवा और ऑक्सीजन का समय पर आवंटन करेगी, जिससे एक भी व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं हो सकेगा। दोनों जजों ने कहा कि राज्य सरकार ऑक्सीजन की मात्रा, परिवहन और दवाओं को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष आंकड़ों सहित मांग पेश करे।

वहीं, केंद्र सरकार एक्टिव मरीजों की संख्या के हिसाब से उस पर तत्काल कदम उठाए । केंद्र सरकार किए गए आवंटन को अगली किस्त में समायोजित भी कर सकती है। कोर्ट ने कहा केंद्र व राज्य सरकार महामारी को लेकर मिलकर बखूबी काम कर रही है। यह समय एक-दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात व भिवाड़ी से ऑक्सीजन दे रही है, लेकिन टैंकर्स की उपलब्धता नहीं होने से ऑक्सीजन परिवहन में परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार एक्टिव मरीजों के अनुपात में न तो ऑक्सीजन दे रही है और न ही आवश्यक दवा उपलब्ध करवा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह समय पर सप्लाई के साथ ही परिवहन के लिए टैंकर उपलब्ध करवाए। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत है। इसी को लेकर इन दिनों राजस्थान हाईकोर्ट सख्त है।

दिवंगत कर्मचारियों के भुगतान में विलंब पर अधिकारियों ने सीएम को लिखा पत्र

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश में दिवंगत कर्मचारियों के स्वत्व के भुगतान में लगातार होते विलंब को लेकर राजपत्रित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें मांग की गई है कि तत्काल राशि का भुगतान हो। साथ ही क्वारंटाइन होते शासकीय सेवकों को 3 दिन का विशेष अवकाश दिया जाए राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डीके यादव द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में बताया गया है कि प्रदेश में दिवंगत कर्मचारी एवं अधिकारियों के स्वत्व के भुगतान में लगातार विलंब हो रहा है।

इस प्रकार की शिकायतें प्रदेश के अन्य जिलों से आई है। इस कारण व्यवस्था ऐसी हो कि दिवंगत कर्मचारी को समय सीमा में राशि का भुगतान होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आवेदन करने के बाद भी कई दिनों तक कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उसके बाद भी राशि नहीं मिल पा रही है। इसके कारण पीड़ित परिवार को बड़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

टीकाकरण के बाद 3 दिन का क्वारेंटाइन अवकाश भी मांगा

उन्होंने बताया है कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री को इस समस्या से अवगत कराया गया है। इसके बाद बुधवार को एक पत्र भी लिख दिया गया है। श्री यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री हर वर्ग का कल्याण करने वाले व्यक्ति हैं। उनके संज्ञान में यह बात आएगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश के दिवंगत कर्मचारियों के पीड़ित परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। निर्धारित समय सीमा में राशि मिलेगी तो परिवारों की आर्थिक गाड़ी भी पटरी पर आएगी।

टीकाकरण के बाद 3 दिन का अवकाश जरूरी: डीके यादव का कहना है कि इस समय पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। कर्मचारी बड़ी संख्या में कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि कई लोगों को टीका लगने के बाद बुखार भी आ रहा है। इस कारण प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री से यह मांग की गई है कि वैक्सीनेशन के बाद 3 दिन का क्वारेंटाइन अवकाश दिया जाए। ताकि अधिकारी और कर्मचारी तनाव मुक्त होकर घर पर आराम कर सके। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा तो निश्चित तौर पर वह समय पर काम पर लौटेंगे।

हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा, घर जाकर दे सकते हैं बुजुर्गों और लाचारों को वैक्सीन

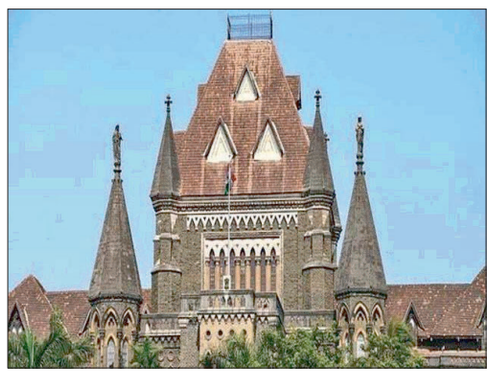

मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा है कि क्या वह वृद्धजनों और लाचार लोगों को घर-घर जाकर कोविड से बचाव वाली वैक्सीन दे सकती है? ये वे लोग हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर में आकर टीका नहीं लगवा सकते।मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) अगर खास वर्ग को घर जाकर वैक्सीन देने के लिए तैयार हो तो हाईकोर्ट इसकी अनुमति देगा। भले ही केंद्र सरकार का इसके लिए कोई प्रविधान न हो। इस बाबत केंद्र की अनुमति के इंतजार की जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार घर-घर जाकर वैक्सीनशन प्रोग्राम चलाए जाने की इच्छुक नहीं है। चीफ जस्टिस दत्ता ने बीएमसी से सवाल किया कि क्या आप वृद्धजनों की सहायता के लिए आगे आएंगे? अगर आप आगे आएंगे तो हम आपको अनुमति देंगे।

हाईकोर्ट ने इस बाबत बीएमसी के कमिश्नर इकबाल चहल से गुरुवार को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है। कहा है कि इसमें बताया जाए कि क्या बीएमसी पूरी सुरक्षा के साथ वृद्धजनों और दिव्यांग/लाचार लोगों का घर जाकर टीकाकरण करने में सक्षम है ? कहा कि महामारी के इस समय में प्रत्येक दिन कीमती है। इसलिए पीठ बिना समय गंवाए गुरुवार को मामले की फिर सुनवाई करेगी। पीठ दो अधिवक्ताओं- ध्रुति कपाड़िया और कुणाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में 75 वर्ष से ज्यादा और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को घर जाकर कोविड से बचाव का टीका लगाने के लिए केंद्र सरकार को आदेश देने की मांग की गई है। मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार टीकाकरण संबंधी अपनी नीति के उन प्रविधानों पर फिर से विचार करे जिनमें कहा गया है कि इस तरह के अभियान से वैक्सीन की बर्बादी होगी और वैक्सीन देने के बाद व्यक्ति पर उसका नकारात्मक असर देखने का समुचित इंतजाम नहीं हो पाएगा।

डीजीपी भास्कर ज्योति महंत ने गुवाहाटी में डीजीपी कॉम्प्लेक्स में एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का स्वागत करते हुए।

स्वास्थ्य सुविधाओं में कश्मीर के आगे कहीं नहीं टिकता जम्मू, यहां हर दिन दम तोड़ रहे मरीज

जम्मू । कोरोना संक्रमण के कारण जम्मू में लगातार हो रही मौतों से एक बार फिर से राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू कठघरे में है। यहां हर दिन औसतन पंद्रह मरीजों की मौत हो रही है। मरीज सुविधाएं कम होने की शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन जम्मू स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमेशा ही कश्मीर के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। कश्मीर के दूरदर्शी नेताओं ने वर्षों पहले ही श्रीनगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर सुविधाएं बना ली थी। लेकिन जम्मू की किसी ने सुध नहीं ली और यहां पर मरीज सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ते रहे।

अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो जम्मू संभाग में डोडा, राजौरी और कठुआ में मेडिकल कालेज बनने से पहले मरीजों के लिए इलाज का एकमात्र विकल्प राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू ही था। अभी भी इन जिलों के अधिकांश मरीज इसी मेडिकल कालेज में आते हैं। जम्मू संभाग की साठ लाख के करीब जनसंख्या पूरी तरह से इसी मेडिकल कालेज पर निर्भर है। जिला और उप जिला अस्पतालों में स्टाफ और सुविधाओं की कमी को पूरा करने में हर कोई विफल रहा है।

श्रीनगर में मेडिकल कालेज के साथ कुल दस अस्पताल हैं। लेकिन जम्मू में पांच ही अस्पताल हैं। श्रीनगर में इन आठ अस्पताल के अलवा एम्स दिल्ली की तर्ज पर बनाया गया शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस सौरा भी है। इसका एक कालेज बेमिना में भी चलता है। लेकिन जम्मू में इस तरह का कोई भी संस्थान नहीं है। अभी जम्मू के विजयपुर में एम्स जरूर बन रहा है। लेकिन इसी तरह का एम्स कश्मीर के अवंतीपोरा में भी बन रहा है।

श्रीनगर में कई वर्ष पहले बच्चों के इलाज के लिए अलग से जीबी पंत अस्पताल बना था। जम्मू में अभी भी इस तरह का कोई अस्पतान न तो बना है और न ही कोई प्रस्ताव है। श्रीनगर में बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल है। जम्मू में यह अस्पताल निर्माणाधीन है लेकिन यह कब बन कर पूरा होगा, इस बारे में कुछ भी नहीं

वहीं अगर बात फैकल्टी की करें तो जीएमसी जम्मू में कुल 387 पद हैं और उनमें से 87 के करीब खाली पड़े हुए हैं। श्रीनगर मेडिकल कालेज में भी चार सौ के आसपास ही फैकल्टी सदस्य हैं लेकिन इनमें से अधिकांश पदों पर नियुक्तियां हुई है। श्रीनगर जीएमसी से मिली जानकारी के अनुसार पंद्रह से बीस पद ही खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ में भी जीएमसी जम्मू में साढ़े तीन सौ के करीब पद खाली पड़े हुए हैं। हालांकि अभी कांट्रेक्ट आधार पर नियुक्तियां जरूर की जा रही हैं।

यही नहीं कोरोना के बहुत से मरीजों को लेवल एक के अस्पतालों की जरूरत पड़ रही है। इन अस्पतालों में बिस्तर न होने के कारण भी मरीजों की जान जा रही है। जम्मू में राजकीय मेडिकल कालेज के अधीन आने वाले अस्पताला में आइसीयू के मात्र 122 ही बिस्तर हें जबकि श्रीनगर मेडिकल कालेज के अधीन आने वाले अस्पतालों में इनकी संख्या तीन सौ के करीब है। राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू के एक वरिष्ठ डाक्टर के अनुसार जम्मू के जीएमसी में इको मशीन तक नहीं है। वह भी महीनों से खराब पड़ी हुई है। यहां पर एचआर सिटी स्कैन करवाना भी बहुत मुश्किल है। जबकि श्रीनगर के अस्पतालों में यह आम स्थिति है।

कोरोना के मरीजों की जांच में चेस्ट डिजिज के डाक्टरों की अहम भूमिका है। जम्मू के सीडी अस्पताल में मात्र तीन ही स्थायी डाक्टर हैं। एक को कांट्रेक्ट पर नियुक्त किया गया है जबकि सीडी अस्पताल श्रीनगर में दस से अधिक डाक्टर हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जम्मू स्वास्थ्य सेवाओं में कितना पिछड़ा हुआ है।

गुजरात में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए तीन दिन और बढ़ा लॉकडाउन

अहमदाबाद । गुजरात में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए गुजरात में आंशिक लॉकडाउन को तीन दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अहमदाबाद, सूरत राजकोट वडोदरा सहित 8 महानगर तथा 28 शहरों में रात्रि कर्फ्यू भी यथावत रहेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसे 31 मई तक बढ़ाने का आग्रह किया। एसोसिएशन का मानना है कि लॉकडाउन के कारण गुजरात में कोरोना पर अंकुश पाया जा सका है।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इस बात की घोषणा की। इससे पहले आंशिक लॉकडाउन 18 मई तक लागू था। नए आदेश के बाद अब आशिंक लॉकडाउन राज्य में 21 मई की सुबह तक रहेगा। इस दौरान मेडिकल डेयरी, राशन, बेकरी, आटा चक्की, सब्जी - फल की दुकान, चश्मे की दुकान अन्य आवश्यक सेवाओं को सुबह 6-00 से शाम को 7-00 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई जबकि मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बाग बगीचे, स्विमिंग पूल, जिम, पार्लर, हेयर ड्रेसर शॉप, सार्वजनिक परिवहन सेवा, सामुदायिक भवन, आदि को बंद रखने का फैसला किया गया।

गुजरात में पिछले चार-पांच दिन से समुद्री तूफान केसर के चलते जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया था इसी कारण 5 दिन के लिए गुजरात में टीकाकरण को भी बंद रखा गया था कि मेडिकल स्टाफ व फार्मेसी कर्मियों की मदद राहत एवं बचाव कार्य में ली जा सके। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को पत्र लिखे कर गुजरात के तीन दर्जन शहरों में लगाए गए रात्रि कर्फ्यू को आगामी 31 मई तक बढ़ाने की अपील की है। इनका मानना है कि इससे गुजरात में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। सरकार अगर लॉकडाउन एवं कर्फ्यू में ढील देती है तो यह फैसला कोरोना वायरस के फैलने में मददगार हो सकता है

फिरौती मामले में छोटा राजन की भतीजी गिरफ्तार

पुणे । अंडरवे र्ल्ड डान छोटा राजन की भतीजी प्रियदर्शिनी निकालजे को पुणे पुलिस ने फिरौती के एक मामले में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी वानोवारिए से की गई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद अंडरवे र्ल्ड डान राजेंद्र निखालजे उर्फ छोटा राजन को इलाज के लिए 26 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था। ठीक होने के बाद उसे 11 मई को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गौरतलब है कि इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार होने के बाद छोटा राजन को 2015 में भारत लाया गया और तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 2011 में पत्रकार जेडे की हत्या के मामले में 2018 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। ठीक होने के बाद गत दिनों उसे एम्स से वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। छोटा राजन का अस्पताल में इलाज चल रहा था। छोटा राजन तिहाड़ के जेल संख्या 2 में है बंद। अस्पताल में 22 अप्रैल को जांच में चला था कोरोना संक्रमण का पता। राजन को 24 अप्रैल को तिहाड़ से एम्स में कराया

गया था दाखिल, यहीं पर उसका इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले इंटरनेट मीडिया में ये सूचना वायरल हो गई थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मौत हो गई है। इस सूचना की जांच की गई तो ये वायरस सूचना गलत निकली। एम्स के एक अधिकारी ने राजन के कोरोना वायरस से संक्रमित होकर इलाज कराने के बारे में पुष्टि की थी।

अप्रैल के आखिरी सप्ताह में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था। कई दिनों तक उसकी हालत स्थिर बनी हुई थी।

छोटा राजन पर अपहरण और हत्या के सहित 70 से अधिक केस दर्ज हैं। उसे मुंबई के सीनियर पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। उसे हनीफ कड़ावाला की हत्या के केस में विशेष सीबीआई कोर्ट ने बरी भी कर दिया था।

मुंबई में 1993 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में भी छोटा राजन आरोपित है। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र निखालजे है। राजन को पुलिस 2015 में इंडोनेशिया से भारत प्रत्यर्पित कर लाया गया है। तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने 26 अप्रैल को एक केस की सुनवाई के दौरान बताया था कि छोटा राजन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पेशी के लिए नहीं लाया जा सकता। इसकी वजह यह है कि उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

राजस्थान में कोरोना के 9849 नए मामले और 139 मौतें, धारा 144 की अवधि 21 जून तक बढ़ी

जयपुर । राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9849 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही 139 पीड़ितों की मौत हुई है। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या एक लाख 53 हजार 126 है। बुधवार को 16039 पीड़ित उपचार के बाद स्वस्थ हुए। सबसे ज्यादा पॉजिटिव 2338 केस जयपुर जिले में मिले हैं। यहां एक दिन में 37 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक आठ लाख 89 हजार 513 कुल संक्रमित मिलने के साथ ही 7219 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच, सरकार ने प्रदेश में धारा 144 की अवधि 21 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी की। प्रदेश में सबसे पहले 22 अप्रैल को 21 मई तक के लिए धारा 144 लागू की गई थी। इसकी अवधि समाप्त होने से दो दिन पहले ही सरकार ने इसे 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया। इसके तहत किसी भी स्थान पर पांच या इससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन 24 मई सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा।

हेल्थ कंसलटेंट की होगी नियुक्ति

इधर, प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कुछ हद तक लगाम लगने लगी है। पिछले तीन दिन से शहरों के स्थान पर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा संक्रमित मिलने लगे हैं। इस कारण सरकार ने ग्रामीण इलाकों में घर-घर सर्वे और दवाओं के किट वितरित करने शुरू किए हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने, कोविड के मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने और मृत्युदर कम करने के लिहाज से प्रदेशभर में कोविड हेल्थ कंसलटेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायक की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। जिला स्तर पर इनका चयन होगा और ये 31 जुलाई तक काम करेंगे। कोविड हेल्थ कंसलटेंट को 39,300 और कोविड स्वास्थ्य सहायक को 7900 मासिक मानदेय दिया जाएगा। हेल्थ कंसलटेंट के लिए एमबीबीएस और स्वास्थ्य सहायक के लिए नर्सिंग की होनी चाहिए। इन्हें घर-घर सर्वे के काम में लगाने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाया जाएगा।

पूजा बिष्ट ने फ्लॉड में अपनी भूमिका के बारे में बताया

अभिनेत्री पूजा बिष्ट ने आगामी वेब-सीरीज 'फ्लॉड' में अपनी भूमिका के बारे में जानकारी दी है। पूजा ने कहा, ''मैं सौम्या का किरदार निभा रही हूं। वह हर किसी की नजर में एक मजबूत, स्वतंत्र लड़की है, लेकिन साथ ही वह अपनी छोटी बहन और मां के साथ उसे छोड़कर दूसरी महिला के लिए अपने पिता की अनुपस्थिति के लिए भी सहन करती है। पूजा के कंधों पर जिम्मेदारी है।'' उन्होंने कहा, ''बस प्यार के विचार ने उसे परेशान कर दिया और इस वजह से वह किसी के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने में असमर्थ है और वह खुद को किसी के लिए खोलना नहीं चाहती है। फिर भी वह अपने जीवन में एक छोटा हिस्सा अपने पिता का चाहती है क्योंकि वह जिम्मेदारियों से थक गई है। टूटे हुए लोगों की खुद की तरह एक आंतरिक खोज उसे समय-समय पर बड़े अज्ञात की ओर ले जाती है।'' इस श्रृंखला में रजनीश दुग्गल, सुमित मानक, अशोक पाठक और सम्राट कपूर भी हैं। इसका निर्देशन धीरज सिंह पडियार ने किया है।

मनोज बाजपेयी हर जगह से दूर, हर जगह

मनोज बाजपेयी इस समय पहाड़ों में हैं और उनका कहना है कि वह हर जगह और हर जगह से दूर हैं। अभिनेता ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर पहाड़ की चोटियों और एक इंद्रधनुष की कई तस्वीरें पोस्ट कीं। हालांकि उन्होंने प्रशंसकों को अपने वर्तमान स्थान के बारे में सूचित करने से परहेज किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''हर जगह और हर जगह से दूर!!!!'' काम की बात करें तो, उन्हें हाल ही में डिजिटल फिल्म ''साइलेंस .कैन यू हियर इट'' में एसीपी अविनाश नाम के एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। इस मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म में प्राची देसाई, अर्जुन माथुर, साहिल वैद, वकार, बरखा सिंह, शिरीष शर्मा, सोहेला कपूर, अमित ठक्कर और गरिमा याज्ञनिक भी हैं। वह जल्द ही लोकप्रिय वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' के दूसरे सीजन में नजर आएंगे।

आदिपुरुष में मेघनाद का किरदार निभा सकते हैं सिद्धार्थ शुक्ला

बिग बॉस 13 के विजेता व अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला अभी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में बने हुए हैं। एक ओर जहां 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3' के ट्रेलर रिलीज की वजह से वो सुर्खियों में हैं तो वहीं दूसरी ओर अब उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर चल रहीं खबरों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला, साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिपुरुष में सिद्धार्थ शुक्ला, मेघनाद का किरदार निभा सकते हैं। हालांकि अभी तक इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर इन खबरों के सामने आने के बाद से ही ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। इस खबर से न सिर्फ प्रभास के फैन्स काफी एक्साइटिड हैं, बल्कि सिद्धार्थ के फैन्स भी खूब उत्साहित हैं। फैन्स का कहना है कि प्रभास और सिद्धार्थ को एक साथ देखना किसी ट्रीट से कम नहीं होगा और फिल्म धमाका करेगी।

नौकरी ठुकराकर फिल्मों में करियर बनाने निकले थे विक्की

विक्की कौशल 33 साल के हो गए हैं। कम समय में ही वो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखने वाले विक्की के पिता शाम कौशल जाने-माने एक्शन डायरेक्टर हैं।

जॉब नहीं करना चाहते थे

विक्की कौशल आज हिंदी फिल्मों का बड़ा नाम बन चुके हैं लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म कर नौकरी करें। वो मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई कर रहे थे तभी एक बार एक आईटी कंपनी में इंडस्ट्रियल दौरे पर गए। वहां पहुंचकर विक्की को एहसास हुआ कि वो ऑफिस जॉब के लिए नहीं बने हैं। इंजीनियरिंग की नौकरी ठुकराने के बाद उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने किशोर नामित कपूर एकेडमी में एडमिशन लिया।

अनुराग कश्यप को किया असिस्ट

अभिनेता बनने से पहले विक्की कौशल ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में काम किया। विक्की निर्देशक अनुराग कश्यप को अपना मेंटॉर मानते हैं। इसके साथ उन्होंने थियेटर करना शुरू किया। अनुराग कश्यप के प्रोडक्शन की फिल्म 'लव शव ते चिकन खुराना' और 'बॉम्बे वेलवेट' में विक्की कौशल छोटे से रोल में दिखे थे।

2015 में आई थी पहली फिल्म

मुख्य अभिनेता के रूप में विक्की कौशल की पहली फिल्म साल 2015 में आई 'मसान' थी। इसे नीरज घेवन ने निर्देशत किया। मसान को समीक्षकों के साथ-साथ दर्शकों ने भी पसंद किया। इसके बाद उन्होंने 'लव पर स्कवॉयर फुट', 'राजी', 'संजू' और 'मनमर्जियां' कीं।

आने वाली फिल्में

साल 2019 में आई 'उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक' विक्की कौशल के करियर की बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म 2016 उरी हमले पर बनी थी। फिल्म को आदित्य धार ने निर्देशित किया। इसके लिए विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। विक्की कौशल की आने वाली फिल्में 'सरदार उधम सिंह' है। इसके अलावा वो 'अश्वत्थामा' और 'सैम बहादुर' में भी दिखेंगे।

अभिषेक बनर्जी ने पाताल लोक में अपनी कास्टिंग का अनुभव किया साझा

एक साल हो गया है जब दुनिया ने अभिषेक बनर्जी को क्राइम-थ्रिलर सीरीज-पाताल लोक में शानदार प्रदर्शन करते हुए देखा था। इस प्रोजेक्ट से पहले कॉमिक भूमिकाओं में अभिनय करने के वाले, अभिषेक ने प्रशंसकों को दिखाया कि दूसरी शैली में भूमिकाएं निभाते समय वह कितने बहुमुखी हो सकते हैं। उन्होंने अब पाताल लोक के दिनों से अपना अनुभव साझा किया है। अपने पाताल लोक के दिनों के बारे में अभिषेक साझा करते हैं, सुदीप सर एक दिन थिएटर में स्त्री देखने गए थे और उन्होंने अगले दिन मुझे यह कहते हुए फोन किया कि वह चाहते हैं कि मैं हाथोदा त्यागी की भूमिका के लिए ट्राय करूं !! उन्होंने कहा, 'उन्होंने मेरी आंखों में एक सनक देखी थी।' यह एक चौंकाने वाला था, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मैंने अपने आप में सनक की तलाश में खुद को आईने में देखा। शुरू में मुझे भूमिका रोमांचक नहीं लगी, त्यागी के पास ज्यादा डायलॉग नहीं थे, यहां तक कि अन्य पात्रों की तुलना में स्क्रीन टाइम भी कम था! मैं ऑडिशन ट्राय करने के लिए ज्यादा खुश नहीं था और साथ ही मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी था, इसलिए एक शर्मनाक स्थिति में नहीं पड़ना चाहता था जहां मुझे टीम से खुद के रिजेक्शन की खबर सुनने को मिले। उन्होंने आगे कहा, हालांकि, कर्णेश सर और सुदीप सर दोनों आश्वस्त थे कि मैं इस किरदार के प्रति अच्छा काम कर सकता हूं। हाथोदा की भूमिका के लिए मैंने उन्हें जो अन्य विकल्प दिए थे, वे उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे! अंत में एक लंबे आंतरिक द्वंद्व के बाद मैंने साहस जुटाया और ऑडिशन दिया! मैंने इसे अपना शतप्रतिशत दिया लेकिन फिर भी घबराया हुआ था जब मैंने आखिरकार उन्हें टेस्ट भेजा। अगली सुबह कर्णेश सर ने फोन किया, मैंने इसे घबराते हुए फोन उठाया और फिर मुझे बताया गया कि उन्हें वास्तव में मेरा ऑडिशन पसंद आया है और मुझे इस किरदार के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है! ओह! यह एक अच्छी राहत थी। लेकिन यह एक कठिन लेकिन खूबसूरत सफर की बस एक शुरूआत थी!! उनके शो पाताल लोक को काफी सराहा गया क्योंकि इसे मजबूत आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है। अभिषेक को उनके हाथोदा सिंह के चित्रण के लिए भी काफी सराहना मिली है। श्रृंखला में उनकी भूमिका ने वास्तव में उन्हें कॉमेडी व्यक्तित्व से मुक्त होने में मदद की, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। वह अब हर निर्देशक की सूची में है जो उन्हें अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए इक्छुक हैं। उनकी हाल ही में रिलीज हुई एंथोलॉजी फिल्म, अजीब दास्तां, अभिषेक के लिए फिर से एक बहुत ही सफल आउटिंग थी क्योंकि वह फिर से अपने चरित्र के सही चित्रण के लिए प्रशंसा का विषय था। हर नए प्रोजेक्ट के साथ वह अपनी कला दिखाते रहते हैं और अपनी काबिलियत साबित करते हैं क्योंकि वह हर बार नई और विविध भूमिकायों को पेश करते हैं। अब उनके पास 5 परियोजनाएं हैं जो पहले से ही डेवलपमेंट स्टेज में हैं। अजीब दास्तान अभिनेता जल्द रश्मि रॉकेट, भेड़िया, आंख मिचोली, दोस्ताना 2 और हेलमेट में दिखाई देंगे।

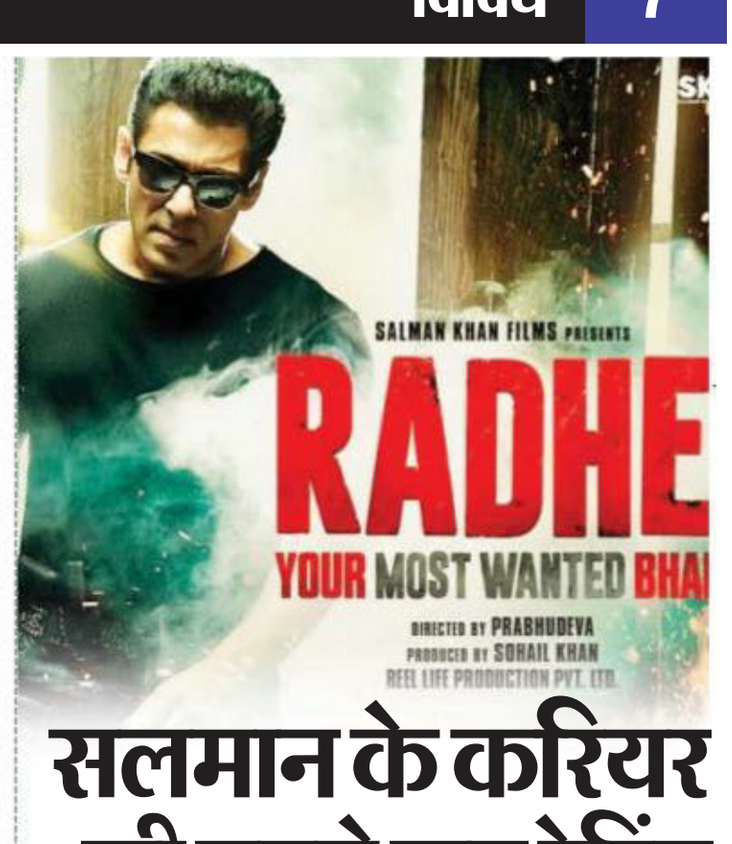

सलमान के करियर की सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म बनी राधे

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई ने उनकी पुरानी फिल्मों की तरह ही रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। एक ओर जहां राधे को तगड़ी व्यूअरशिप मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर फिल्म की रेटिंग भी गिरती जा रही है।

1.8 रेटिंग

सलमान खान की राधे योर मोस्ट वांटेड को करीब 93 हजार रेटिंग्स के आधार पर एवरेज 18 रेटिंग मिली है। रेटिंग में करीब 70 हजार लोगों ने फिल्म को एक स्टार दिया है, जबकि करीब साढ़े 9 हजार लोगों ने 10 रेटिंग्स। बता दें कि ये एवरेज रेटिंग, यूजर्स के रिव्यू के मुताबिक आने वाले वक्त में कम ज्यादा भी हो सकती है।

पहले से गिरी रेटिंग

वैसे राधे की रेटिंग को लेकर जो बड़ी बात सामने आई है वो ये कि फिल्म की रेटिंग कुछ वक्त पहले तक 10 में से 24 थी, वहीं इसके बाद रेटिंग 19 हुई और अब रेटिंग 18 हो गई है। वहीं 18 के साथ ही राधे, सलमान खान के करियर की सबसे कम रेटिंग फिल्म बन गई है। बता दें कि राधे के बाद सलमान के करियर की सबसे कम रेटिंग में रेस 3 का नाम आता है।

ट्वीट कर सलमान ने की अपील

सलमान खान ने फिल्म को पायरेटेड साइट्स पर नहीं देखने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि साइबर सेल अपराधियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाएगा। सलमान ने एक ट्वीट कर अपनी ये बात कही है। सलमान लिखते हैं कि 'हमने आपको 249 रुपये प्रति व्यू के उचित मूल्य पर हमारी फिल्म राधे को देखने के लिए उपलब्ध कराया है। इसके बावजूद पायरेटेड साइट्स राधे की अवैध रूप से स्ट्रीमिंग कर रही हैं जो कि एक गंभीर अपराध है। साइबर सेल इन सभी अवैध पायरेटेड साइट्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। कृपया पायरेसी का हिस्सा ना बनें नहीं तो साइबर सेल आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। कृपया समझें कि आप साइबर सेल के साथ बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे।'

पहले भी वीडियो किया था पोस्ट

सलमान खान ने इससे पहले एक वीडियो साझा कर प्रशंसकों से पाइरेटेड साइट्स से फिल्म नहीं देखने की अपील की थी। वीडियो में सलमान कहते हैं कि 'एक फिल्म बनाने में बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं। बहुत दुख होता है जब लोग पाइरेसी करके एक फिल्म देखते हैं। मैं आप सबसे एक कमिटमेंट मांगता हूं कि फिल्म एंजॉय करें। सही प्लेटफॉर्म पर तो ये होगा दर्शकों का कमिटमेंट- नो पाइरेसी इन एंटरटेनमेंट।'

अगर कोई भविष्य है तो यह हरा होगा

अभिनेत्री क्रिस्टल डिसूजा ने शनिवार को अपने नए इंस्टाग्राम पोस्ट में कोविड-19 के कारण फैली तमाम निराशाओं के बीच पर्यावरण के अनुकूल आशावाद को फैलाया। 'अगर कोई भविष्य है तो यह हरा होगा,' उन्होंने हरे दिल वाले इमोजी के साथ लिखा, एक छवि है जिसमें वह हरियाली के बीच एक गाउन जिसे वह स्टाइलिश रूप से डेनिम शॉर्ट्स के ऊपर पहनी है। अभिनेत्री को हाल ही में भरत गोयल के गाने 'एक बेवफा' के रीक्रिएटेड वर्जन में देखा गया था। यह नंबर मूल रूप से सोनू निगम द्वारा 2005 में अक्षय कुमार-करीना कपूर की फिल्म 'बेवफा' में गाया गया था। रीक्रिएटेड गाने के म्यूजिक वीडियो में वह सिद्धार्थ गुप्ता और अक्षय खरोदिया के साथ नजर आ रही हैं।

राधे फिल्म में लुक को लेकर सलमान खान ने काफी सहायता की

फिल्म राधे : योर मोस्ट वांटेड भाई में गिरगिट की भूमिका निभाने वाले अभिनेता गौतम गुलाटी ने याद किया है कि कैसे फिल्म के मुख्य अभिनेता सलमान खान ने उनके लुक को तय करने में विशेष रुचि ली। गौतम कहते हैं कि उन्होंने ओटीटी पर शो देखे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके अपने कैरेक्टर की बारीकियां सही हैं। उन्होंने कहा, ''मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई शो देखे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नकारात्मक चरित्र के शेड्स को कैसे निखारा जाए, लुक से लेकर एक्सप्रेशन तक और भी बहुत कुछ। फिर, मैंने सलमान सर के विश्वास के साथ गिरगिट में अपने शेड्स जोड़े और इस तरह यह चरित्र जीवन में लाया गया।'' अभिनेता ने कहा कि उन्होंने एक्शन वश्यों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण भी लिया। उन्होंने यह बात भी साझा की कि कैसे सलमान खान ने इस फिल्म में उनके लुक को लेकर काफी सहायता की। अभिनेता ने कहा, टैटू और बाल कटवाने की अवधारणा भी सलमान सर ने ही तय की थी और मुझे खुशी है कि हमने इसका पालन आखिर तक किया। एक्शन वश्यों के लिए बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और कई बार तो यह सुबह से रात तक चलती है। यह फिल्म हाल ही में भारत में एक डिजिटल पे-पर-व्यू प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है।

टी-20 वर्ल्डकप 2021: वर्ल्ड कप में सभी टीमें टी20 के ज्यादा अनुभव के साथ उतरेंगी; हमारे पास सिर्फ 3 मैच का मौका

नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में करीब 150 दिन बचे हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत अक्टूबर के मध्य में होगी। भारत के पास टूर्नामेंट की मेजबानी है। लेकिन कोरोना की वजह से उसे यूएई शिफ्ट किया जा सकता है। वेस्टइंडीज सबसे सफल टीम होने के साथ ही डिफेंडिंग चैंपियन भी है। टीम ने वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है।

कीरोन पोलार्ड की कप्तानी वाली टीम 26 जून से 3 अगस्त के बीच 15 टी20 इंटरनेशनल खेलेगी। द. अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान से 5-5 मैच। पहले विंडीज और पाक के बीच 3 टी20 और 3 टेस्ट होने वाले थे। लेकिन वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए दोनों बोर्ड ने एक टेस्ट की जगह दो टी20 खेलने का फैसला किया। फिर उनकी घरेलू टी20 लीग (सीपीएल) होनी है। अगर सितंबर में आईपीएल होता है तो खिलाड़ी उसमें भी खेलेंगे। कई विंडीज खिलाड़ी लीग के लिए इंटरनेशनल छोड़ देते हैं। लेकिन सभी टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में वापस लौट आते हैं। लीग में वे दुनिया के प्रमुख खिलाड़ियों के खिलाफ काफी खेल चुके होते हैं, जिसका इंटरनेशनल में फायदा मिलता है।

टी20 वर्ल्ड कप के करीब एक महीने पहले तक भारतीय टीम इंग्लैंड में टेस्ट खेल रही होगी। हालांकि जुलाई में व्हाइट बॉल सीरीज का श्रीलंका दौरा है। लेकिन उसमें कप्तान कोहली और उपकप्तान रोहित समेत कई प्रमुख खिलाड़ी नहीं होंगे। श्रीलंका में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दौरे की स्थिति साफ नहीं है। इंग्लैंड की टेस्ट और टी20 टीम पूरी तरह अलग है। टी20 के विशेषज्ञ खिलाड़ी द हंड्रेड लीग खेल रहे होंगे। उससे पहले टी20 ब्लास्ट भी है। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम पाकिस्तान और श्रीलंका से 3-3 टी20 खेलेगी। अगर सितंबर में स्थगित हुए आईपीएल के 31 मैच नहीं होते हैं तो भारतीय टीम को बिना टी20 मैच की प्रैक्टिस के वर्ल्ड कप में उतरना पड़ेगा।

टी-20 वर्ल्ड कप से पहले अफ्रीकी टीम को झटका: सीएसए ने कहा- एबी डिविलियर्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे

नई दिल्ली। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया की दिग्गज बैट्समैन एबी डिविलियर्स टी-20 वर्ल्ड कप के लिए संन्यास वापस नहीं लेंगे। सीएसए ने कहा कि डिविलियर्स ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा कि वे संन्यास के फैसले पर अटल हैं। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का कोई प्लान नहीं है। इससे पहले मी. 360 के नाम से मशहूर डिविलियर्स IPL 2021 में शानदार फॉर्म में थे।

उन्होंने 7 मैच में 164.28 के स्ट्राइक रेट से 207 रन बनाए थे। इसमें 2 ताबड़तोड़ फिफ्टी भी शामिल है। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि डिविलियर्स अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए वापसी कर सकते हैं। उन्होंने खुद टूर्नामेंट के बीच में साउथ अफ्रीकी टीम के डायरेक्टर मार्क बाउचर से इस बारे में बात करने की बात कही थी। वहीं, टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री समेत कई पूर्व क्रिकेटर्स ने उनसे इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने की मांग की थी। डिविलियर्स ने इंटरनेशनल करियर में 114 टेस्ट में 50.66 की औसत से 8765 रन बनाए। वहीं, 228 वनडे में उनके नाम 53.5 की औसत से 9577 रन हैं। उन्होंने 78 टी-20 भी खेले, जिसमें उन्होंने 26.12 की औसत और 135.17 के स्ट्राइक रेट से 1672 रन बनाए। IPL में भी उनके नाम 5056 रन हैं।

टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल: कीवी कप्तान विलियम्सन बोले- भारत की चुनौती स्वीकार

वेलगिंटन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। इससे पहले कीवी कप्तान केन विलियम्सन ने टीम इंडिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वे फाइनल में भारत की चुनौती स्वीकार करते हैं। यह मैच मजेदार होने वाला है। वहीं, न्यूजीलैंड के ही तेज गेंदबाज नील वैगनर ने कहा है कि भारत का पेस बॉलिंग अटैक कीवी बल्लेबाजों के लिए परेशानी बन सकते हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने विलियम्सन का एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में विलियम्सन कहते हैं- जब भी हम भारत के खिलाफ खेलते हैं, वह मैच चैलेंजिंग होता है। उनके खिलाफ खेलना मजेदार होता है। फाइनल में दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ खेलना शानदार रहेगा। अगर हम इसे जीत पाए तो यह और भी बेहतर होगा। मेरी टीम इस मैच को लेकर तैयार है। विलियम्सन ने कहा- WTC की वजह से टेस्ट मैच भी अब दिलचस्प होने लगे हैं। अब मैचों में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज और पाकिस्तान-न्यूजीलैंड सीरीज इसका एक शानदार उदाहरण है। अब रिजल्ट के लिए दोनों टीमों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वहीं, कीवी तेज गेंदबाज वैगनर ने कहा कि भारतीय पेस अटैक शानदार है। पर मैच और पिच कंडिशन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारतीय तेज गेंदबाजी में क्वॉलिटी है और उन्होंने अलग-अलग कंडिशन में खुद को साबित भी किया है। वे ओवरकास्ट कंडिशन (बादल) में बॉल स्विंग कराने में माहिर हैं। पर धूप और फ्लैट विकेट पर वे स्ट्रगल करते हैं। इसका फायदा हमारे बल्लेबाज उठा सकते हैं।

टेनिस: दुनिया के 75वें नंबर के खिलाड़ी पाब्लो से हारे फेडरर

- क्ले कोर्ट पर यह पिछले दो साल में पहला मुकाबला था रोजर का
- 08 साल और 32 जीत के बाद बाद फेडरर ने अपने देश स्विट्जरलैंड में कोई मैच हारा

लंदन। दो साल बाद क्ले कोर्ट पर उतरे बीस बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर को पहले ही मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले दौर में बाई पाने वाले स्विट्जरलैंड के 39 वर्षीय फेडरर को जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में दुनिया के 75वें नंबर के खिलाड़ी पाब्लो एंडूजर ने 4-6, 6-4, 4-6 से उलटफेर का शिकार बनाया। इस हार के साथ फेडरर का अपने देश में 32 मैचों से चला आ रहा विजय रथ भी थम गया। उन्हें स्विट्जरलैंड में पिछली हार आठ साल पहले (27 अक्तूबर 2013 को) बासेल ओपन के फाइनल में जुआन मार्टिन डेल पोत्रो के हाथों मिली थी। यह फेडरर का इस साल का दूसरा टूर्नामेंट था। स्पेन के पाब्लो ने पांचवीं बार शीर्ष दस में शुमार किसी खिलाड़ी को हराया। क्वार्टर फाइनल में अब पाब्लो का सामना स्थानीय खिलाड़ी डोमिनिक

स्टीफन स्ट्राइकर से होगा। दुनिया के 419वें नंबर के खिलाफ स्ट्राइकर ने क्रोएशिया के मारिन सिलिच को 7-6, 6-1 से बाहर का रास्ता दिखाया।

तेईस बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स एमिलिया रोमागना ओपन के दूसरे दौर में ही हारकर बाहर हो गईं। शीर्ष वरीयता प्राप्त 39 वर्षीय सेरेना को कैटरीना सिनिकोवा के हाथों 6-7, 2-6 से शिकस्त मिली। इस हार से सेरेना की दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन की तैयारियों को झटका लगा है। रोलां गैरां 30 जून से पेरिस में शुरू होगा।

एशियाई चैंपियनशिप: विकास और अमित को टीम में मिली जगह, 21 को रवाना होगी टीम

नई दिल्ली। गत चैंपियन अमित पंघाल (52 किग्रा) और विकास कृष्ण (69 किग्रा) समेत ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके ज्यादातर मुक्केबाजों को दुबई में 24 मई से शुरू होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

महिला टीम में छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम (51 किग्रा) सहित टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने वाली सभी चार खिलाड़ियों को जगह मिली है। यात्रा के लिए जरूरी स्वीकृति मिलने के बाद टीम 21 मई को दुबई रवाना होगी। इस चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को करनी थी लेकिन कोविड-19 के कारण इसे दुबई स्थानांतरित किया गया।

भारत सह आयोजक बना रहेगा। टोक्यो का टिकट कटाने वाले मनीष कौशिक (63 किग्रा) और सतीश कुमार (+91 किग्रा) को टीम में शामिल नहीं किया गया है। यह दोनों कोरोना संक्रमण से उबर रहे हैं। पांच पुरुष मुक्केबाजों ने जुलाई-अगस्त में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। कौशिक की जगह चार बार के एशियन पदक विजेता शिव थापा और सतीश की जगह नरेंद्र को शामिल किया गया है।

टीम : पुरुष : विनोद तंवर (49 किग्रा), अमित पंघाल (52 किग्रा), मोहम्मद हुसामुद्दीन (56 किग्रा), वरिंदर सिंह (60 किग्रा), शिव थापा (64 किग्रा), विकास कृष्ण (69 किग्रा), आशीष कुमार (75 किग्रा), सुमित सांगवान (81 किग्रा), संजीत (91 किग्रा) और नरेंदर (91 किग्रा से अधिक)।

महिला : मोनिका (48 किग्रा), मैरीकॉ (51 किग्रा), साक्षी (54 किग्रा), जास्मिन (57 किग्रा), सिमरनजीत कौर (60 किग्रा),

लालबुआतसाही (64 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (69 किग्रा), पूजा रानी (75 किग्रा), स्वीटी (81 किग्रा) और अनुपमा (81 किग्रा से अधिक)।

बैकस्ट्रोक स्पर्धा : तैराक क्लिमेंट ने तीन साल पुराना अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा

- 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में निकाला 23.93 सेकंड का समय
- 24 सेकंड से कम समय में यह दूरी नापने वाले दुनिया की पहले तैराक बने

नई दिल्ली। रशियन तैराक क्लिमेंट कोलेसनिकोव ने 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में अपना ही तीन साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीस वर्षीय क्लिमेंट ने यूरोपियन चैंपियनशिप में 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा के सेमीफाइनल में 23.93 सेकंड का समय निकालकर अपने पिछले रिकॉर्ड में 0.07 सात सेकंड का सुधार किया। उन्होंने 2018 में ग्लास्गो में यूरोपियन चैंपियनशिप में 24 सेकंड के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तब उन्होंने छह पदक जीते थे जिसमें तीन स्वर्ण थे। हालांकि 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा मौजूदा ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं है।

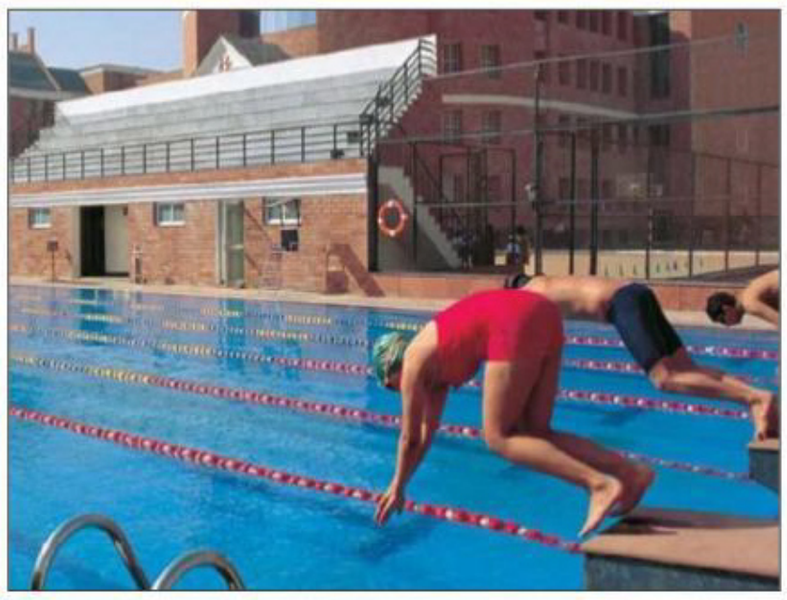

50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में निकाला 23.93 सेकंड का समय

वाह, यह अविश्वसनीय एहसास है। मैं विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में सोच रहा था, पर मैंने उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। मैं सिर्फ तैरने और पहले स्थान के बारे में सोच रहा था। - क्लमेंट कोलेसनिकोव

अनुदान: जोसेफ को खेल मंत्रालय से मिली 2.5 लाख रुपये की सहायता, थे कोरोना से संक्रमित

- खेल मंत्रालय नेजोसेफ जेम्स को 2.5 लाख रुपये की दी सहायता
- एशियाई पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता जेम्स हो गए थे कोरोना से संक्रमित

नई दिल्ली। खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग कोच जोसेफ जेम्स को 2.5 लाख रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी है। वह हाल में कोरोना से ठीक हुए हैं। खेल मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर कहा, 2008 एशियाई पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता जेम्स को खिलाड़ियों के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष से राशि स्वीकृत की गई है।

बता दें कि कुछ दिन पहले कोविड-19 संक्रमण का शिकार होने के बाद 24 अप्रैल को जेम्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आक्सीजन का स्तर गिरने के बाद जेम्स को हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें लगभग एक हफ्ते आईसीयू में रखा गया।

एशियाई खेल 2006 के चैंपियन की हालत अब स्थिर है और वह घर लौट चुके हैं। जेम्स की बेटी एलिका जो ने मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ को समय पर वित्तीय मदद के लिए धन्यवाद दिया है।

भारत का सबसे मुश्किल चैलेंज इंग्लैंड दौरा:पिछले 10 साल में टीम इंडिया को इंग्लैंड में सबसे ज्यादा हार मिली

यहीं भारत को टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और 5 टेस्ट खेलना है

मेलबर्न। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अगला 4 महीना काफी चैलेंजिंग रहने वाला है। टीम इंग्लैंड दौरे पर जा रही है, जहां पहले उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलना है। इसके बाद टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलेगी। WTC फाइनल 18 से 22 जून के बीच साउथैम्प्टन में खेला जाएगा। वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत 4 अगस्त से होगी। भारत के लिए यह दौरा आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि टीम को पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा हार इंग्लैंड की धरती पर ही मिली है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड में इस दौरान 14 टेस्ट खेले हैं। इसमें से 11 में भारत को हार का सामना करना पड़ा और वह सिर्फ 2 ही मैच जीत सकी।

भारत के लिए सबसे मुश्किल रहने वाले SENA के बाकी देशों की बात करें, तो टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 साल में 16 टेस्ट खेले हैं। इसमें से 8 मैच में टीम इंडिया को हार मिली और 4 मैच में जीत दर्ज की। वहीं, न्यूजीलैंड दौरे पर भारत ने 4 टेस्ट खेले, जिसमें से 3 में हार मिली और 1 ड्रॉ रहा। साउथ अफ्रीका में भारत ने 8 टेस्ट खेले, जिसमें से 2 में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा। 2 टेस्ट ड्रॉ रहे। भारत ने इंग्लैंड में अब तक कुल 62 टेस्ट खेले हैं। इसमें से 7 में टीम को जीत मिली और 34 में हार का सामना करना पड़ा। 21 टेस्ट ड्रॉ रहे। पिछले 10 साल की बात की जाए, तो भारत ने 2011, 2014 और 2018 में इंग्लैंड का दौरा किया था।

एशेज सीरीज का शेड्यूल जारी

8 दिसंबर को गाबा में खेला जाएगा पहला मैच; 26 साल में पहली बार फाइनल मुकाबला सिडनी की जगह पर्थ में होगा

मेलबर्न। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली बहुचर्चित एशेज सीरीज की शुरुआत 8 दिसंबर से होगी। पहला टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाएगा। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 14 जनवरी से पर्थ में होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम सभी फॉर्मेट में होने वाली एशेज ट्रॉफी का इकलौता टेस्ट 27 जनवरी से खेलेगी। मेन्स फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैम्पियन है।

26 साल बाद ऐसा हो रहा है कि पर्थ में आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। पिछली बार 1995 में सीरीज का आखिरी मैच सिडनी की जगह पर्थ में खेला गया था। ब्रिस्बेन और पर्थ के अलावा सीरीज के बाकी 3 मैच एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में खेले जाएंगे।

गाबा में ऑस्ट्रेलिया को 32 साल बाद भारत से हार का सामना करना पड़ा

ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड के खिलाफ अभियान की शुरुआत जिस गाबा से करेगी, वहां इसी साल भारत ने उनके 32 साल के पराक्रम को तोड़ा था। भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम की थी।

ऑस्ट्रेलिया को इससे पहले 1988 में वेस्टइंडीज ने गाबा में 9 विकेट से हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने गाबा मैदान पर अब तक 56 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से उसने 33 जीते हैं। जबकि 13 ड्रॉ रहे हैं और केवल नौ में ही उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, एक मैच टाई रहा है।

एशेज से पहले ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा वॉर्मअप मैच

इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम अफगानिस्तान के साथ 27 नवंबर को एक टेस्ट मैच खेलेगी। अफगानिस्तान को 2018 में टेस्ट का दर्जा मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया का उनके खिलाफ यह पहला मैच होगा। अब तक अफगानिस्तान ने केवल 6 टेस्ट मैच भारत, आयरलैंड, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ ही खेले हैं। सीरीज का दूसरा मैच एडिलेड में डे-नाइट होगा।

एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप

पहली बार 4 लाख डॉलर इनामी राशि की घोषणा, 24 मई से शुरू होगा टूर्नामेंट

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (एआईबीए) ने दुबई में आगामी एशियाई चैंपियनशिप के लिए मंगलवार को चार लाख डॉलर की इनामी राशि की घोषणा की। इस प्रतियोगिता में भारत के भी शीर्ष मुक्केबाज हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट का आयोजन शुरुआत में भारत में होना था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे दुबई में स्थानांतरित किया गया। पुरुष और महिला मुक्केबाजों की यह प्रतियोगिता 24 मई से शुरू होगी।

एआईबीए ने बयान में कहा, %पुरुष और महिला दोनों वर्ग में शीर्ष पर रहने वाले मुक्केबाज को 10 हजार डॉलर की राशि मिलेगी। दूसरे स्थान पर रहने वाले मुक्केबाज को पांच हजार डॉलर जबकि कांस्य पदक विजेता को ढाई हजार डॉलर मिलेंगे। भारतीय चुनौती की अगुआई महिला वर्ग में छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम (51 किग्रा) करेंगी जबकि पुरुष वर्ग में चुनौती का दारोमदार गत चैंपियन अमित पंघाल (52 किग्रा) पर होगा।

अमित और विकास भारतीय पुरुष टीम में शामिल

विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेत और गत चैंपियन अमित पंघाल (52 किग्रा) सहित ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले अधिकतर भारतीय पुरुष मुक्केबाजों ने दुबई में एशियाई चैंपियनशिप के लिए टीम में अपनी जगह बनाई। यात्रा के लिए जरूरी स्वीकृति मिलने के बाद भारतीय दल 21 मई को रवाना होगा।

टोक्यो के लिए क्वालीफाई करने वाली चारों मुक्केबाजों को टीम में जगह

पिछले महीने घोषित महिला टीम की अगुआई छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम (51 किग्रा) करेंगी। टोक्यो के लिए क्वालीफाई करने वाली चारों मुक्केबाजों को टीम में जगह मिली है, जिसमें सिमरनजीत कौर (60 किग्रा) भी शामिल हैं जो हाल में कोविड-19 से उबरी हैं।

एशियाई चैंपियनशिप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

भारत ने थाईलैंड में 2019 में हुई एशियाई चैंपियनशिप में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण, चार रजत और सात कांस्य पदक सहित 13 पदक जीते थे। टूर्नामेंट के लिए चुने गए खिलाड़ियों का नियमित तौर पर आरटी-पीसीआर परीक्षण होगा और वे पटियाला, पुणे और बंगलूरू में जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में ट्रेनिंग कर रहे हैं।

कोरोना महामारी के कारण दुबई में शिफ्टइस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में ही होना था लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे दुबई स्थानांतरित कर दिया गया लेकिन भारत ने सह मेजबान का अधिकार बरकरार रखा है। टूर्नामेंट की शुरुआत 24 मई हो होगी जबकि ड्रॉ 23 मई को होगा। अंतरराष्ट्रीय यात्रा पाबंदियों के कारण टीम की रवानगी की योजना खटाई में पड़ती दिख रही थी लेकिन यूएई के अधिकारियों ने मंगलवार को स्वीकृति दे दी।

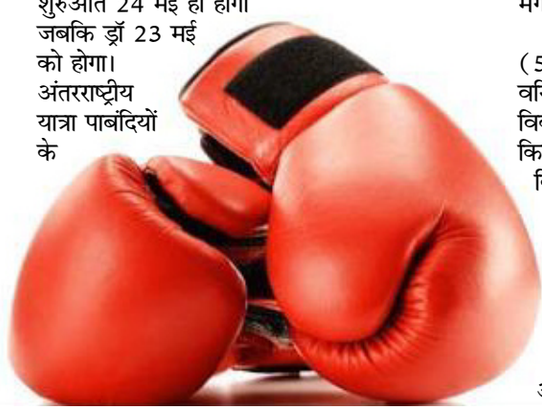

पुरुष: विनोद तंवर (49 किग्रा), अमित पंघाल (52 किग्रा), मोहम्मद हुसामुद्दीन (56 किग्रा), वरिंदर सिंह (60 किग्रा), शिव थापा (64 किग्रा), विकास कृष्ण (69 किग्रा), आशीष कुमार (75 किग्रा), सुमित सांगवान (81 किग्रा), संजीत (91 किग्रा) और नरेंदर (91 किग्रा से अधिक)।

महिला: मोनिका (48 किग्रा), एमसी मेरकोम (51 किग्रा), साक्षी (54 किग्रा), जास्मिन (57 किग्रा), सिमरनजीत कौर (60 किग्रा), लालबुआतसाही (64 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (69 किग्रा), पूजा रानी (75 किग्रा), स्वीटी (81 किग्रा) और अनुपमा (81 किग्रा से अधिक)।